राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 30 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-208 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

नेपाल-तिब्बत सीमा पर महाप्रलय में महाराष्ट्र के 200 से 400 नागरिक फंसे, 60 के लापता होने की आशंका

मुंबई (एजेंसी)। नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच महाराष्ट्र के करीब 200 से 400 नागरिकों के फंसे होने का अनुमान है। इनमें से करीब 100 से 125 लोगों का एक समूह सुरक्षित बताया जा रहा है। यह समूह मानसरोवर की ओर आगे बढ़ रहा है या फिर वहां से वापसी के मार्ग पर है। हालांकि, सीमा क्षेत्र में सड़कें और इमिग्रेशन पोस्ट बह जाने के कारण इन यात्रियों की सुरक्षित वापसी बड़ी चुनौती बन गई है। नेपाल और चीन की सरकारें उनके लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने में जुटी हैं। अखिल महाराष्ट्र गिर्यारोहण महासंघ के अध्यक्ष उमेश झिरपे ने कहते हैं कि वे प्रभावित यात्रियों और कुछ गिर्यारोहकों के लगातार संपर्क में हैं। उनके अनुसार, मुंबई से गए एक समूह के करीब 60 लोगों के लापता होने की आशंका है। इस समूह में महाराष्ट्र के नागरिकों के अलावा कुछ अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं। वहीं, अब तक करीब 105 नागरिकों के सुरक्षित रूप से भारत लौटने की जानकारी सामने आई है। सीमा क्षेत्र में लगातार खराब मौसम और बाढ़ के कारण राहत एवं बचाव अभियान बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। कई स्थानों पर संपर्क मार्ग और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। प्रभावित लोगों के परिजन भी चिंता में हैं। महाराष्ट्र से लापता नागरिकों के कई रिश्तेदार नेपाल की ओर रवाना होने लगे हैं। इस बीच, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए विशेष सहायता कक्ष शुरू किया है। दूतावास और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से फंसे हुए लोगों की जानकारी जुटाने तथा उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उमेश झिरपे ने कहा कि प्रभावित तीर्थयात्रियों और नागरिकों की तलाश, बचाव कार्य तथा आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए संबंधित प्रशासन और आपातकालीन एजेंसियां पूरी ताकत से काम कर रही हैं। अत्यंत चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच अभियान चलाया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी प्राकृतिक संकट का खतरा बना हुआ है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई वंदे भारत एक्सप्रेस, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

हजारीबाग (एजेंसी)। हजारीबाग में देर रात चरही और बेस रेलवे स्टेशन के बीच रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस दुर्घटना की शिकार हो गई। पटरी पर अचानक आई एक लकड़ी से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से ट्रेन टकरा गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बाल-बाल बच गया। जानकारी के मुताबिक हादसा इतना जोरदार था कि टक्कर के बाद ट्रेन को थोड़ा नुकसान हुआ। घटना के तुरंत बाद ट्रेन पायलट ने मुस्तैदी दिखाते हुए गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 41 मिनट तक दुर्घटनास्थल पर ही खड़ी रही। घटना की जानकारी तुरंत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस को दी गई। ट्रेन रुकने के बाद तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रेन की जांच की। सुरक्षा मानकों को पूरा करने और रूट क्लियर होने के बाद ट्रेन को पटना के लिए रवाना किया गया। हादसे के कारण ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रक-पिकअप की टक्कर, आग लगने से चालक जिंदा जला

झाबुआ (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दिल्ली-मुंबई 8-लेन एक्सप्रेसवे के पहुंच मार्ग पर शुक्रवार रात ट्रक और पिकअप वाहन की आमने-सामने जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई जिसमें पिकअप चालक जिंदा जल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात एक ट्रक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही पिकअप से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में दोनों वाहनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गईं और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में पिकअप चालक को वाहन से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। वह वाहन के अंदर ही फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मियाटी निवासी तेरु खिमा भाबर के रूप में हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद वहां जाम लगा गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने घटनास्थल पर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया। साथ ही हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि एक्सप्रेस-वे के पहुंच मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण यहां वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है। सड़क पर एक साथ दोनों दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इस मार्ग पर लगातार हादसे होने से क्षेत्रवासियों में चिंता बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से एक्सप्रेस-वे के पहुंच मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने, यातायात व्यवस्था को बेहतर करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है।

कोई और प्रकाशक ढूंढ लेते, इसमें सरकार को बीच में लाने की क्या जरूरत है?

सोनिया गांधी की किताब को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार

नई दिल्ली, एजेंसी।
सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग से जुड़े विवाद में सरकार पर कांग्रेस के हमलों को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह लेखक और प्रकाशक के बीच का विवाद है। सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग को छापने से प्रकाशक कंपनी पेंगुइन इंडिया ने मना कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कहा कि लेखक और प्रकाशक के बीच में कहीं किसी तरह का अंतरविरोध है। प्रकाशक का अपना प्रॉरोगेटिव है और लेखक का अपना व्यूपॉइंट है। उसको राजनीति में लाने के बजाय किसी और प्रकाशक ढूंढ लेते, इसमें भारत सरकार को बीच में लाने की क्या जरूरत है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे सरकार पर दबाव के आरोप क्यों लगा रहे हैं। पेंगुइन इंडिया और रैंडम हाउस इंडिया ने साफ कर दिया है कि यह किताब उनकी नहीं है। अब इसके पीछे क्या मकसद था, यह तो वे या सोनिया गांधी समझ सकती हैं। अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने साफ कहा था कि वे कुछ हिस्सों को हटाने की कोशिश कर रहे थे और सोनिया गांधी इससे सहमत नहीं थीं। यह पब्लिशर और लेखक के बीच का विवाद है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, जब प्रकाशक को कुछ चीजें नहीं छापनी होती हैं तो वह अपनी आपत्ति दर्ज करता है। इसमें सरकार का रोल कहां से आया?
उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को यह देश को बताना चाहिए कि वह विवादित अंश क्या था। क्या उन्होंने अपनी सास के बारे में कुछ लिख दिया था? क्या अपने देवर के बारे में कुछ ऐसी चीजें लिखीं, जो उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थीं। या कुछ और बात है, जो पेंगुइन ने कहा है। उन्होंने कहा कि इस पर सोनिया गांधी खामोश हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब भी कोई किताब प्रकाशित होती है, तो वह प्रकाशक और लेखक के बीच के रिश्ते पर आधारित होती है और दोनों की ही मिली-जुली जिम्मेदारी होती है। किताब में दिए गए तथ्यों और कंटेंट के लिए दोनों ही जिम्मेदार होते हैं।
वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि हमें नहीं पता कि असलियत क्या है। सोनिया गांधी की किताब को लेकर किसने दबाव डाला। पेंगुइन ने क्या किया या क्या नहीं किया। इस पर चर्चा तो हुई है, लेकिन हमें असल बात नहीं पता। बीजेपी नेता टीआर श्रीनिवास ने कहा कि यह सोनिया गांधी की किताब है, जिसे पेंगुइन को प्रकाशित करना था। इसका समय राजनीतिक और गैर-साहित्यिक लगता है। पेंगुइन ने आपत्ति जताई है, क्योंकि जब भी आप कोई किताब प्रकाशित करते हैं, तो उसमें तथ्य सही होने चाहिए।

ममता बनर्जी के पास कोई विचारधारा नहीं : शिवसेना ने साधा निशाना

मुंबई (एजेंसी)। शिंदे शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी ने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कड़ा हमला बोला है, यह कहकर कि उनके पास कोई विचारधारा और विजन प्लान नहीं है। ममता के वोट चोरी के आरोपों को खारिज कर शिंदे शिवसेना की प्रवक्ता शाइना ने उन्हें बेबुनियादी आरोप लगाने की बजाय अपने मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दे दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और फर्जी तथा डबल मतदाताओं को हटाना सामान्य एवं आवश्यक प्रक्रिया है। शाइना एनसी ने कहा कि ममता बनर्जी इसतरह के बेबुनियादी आरोप लगाती रहेंगी।
इसके अलावा, एनसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में आयोजित कार्यक्रम को भारत के लिए गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लाखों भारतीय रहते हैं और संघ का वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश भारत की विश्व में नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। उन्होंने संघ को राष्ट्रवाद और सेवा के लक्ष्य वाला 100 साल पुराना सांस्कृतिक संगठन बताया। नेपाल में आई भीषण त्रासदी पर शिवसेना प्रवक्ता ने भारत की निरंतर मदद को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास लगातार संवाद में हैं, और महाराष्ट्र के नेताओं एकनाथ शिंदे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्य के पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने प्राकृतिक आपदा को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भविष्य के लिए हम सावधान रहें। नेपाली प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का स्वागत कर शाइना ने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों के महत्व को दोहराया और कहा कि वर्तमान में नेपाल की मदद करना सर्वोपरि है।

एमएलसी मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकाला

-एआईएमआईएम ने तत्काल इस्तीफा देने के दिए निर्देश

हैदराबाद, एजेंसी।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने शुक्रवार व शनिवार रात यह कार्रवाई करते हुए बेग को तत्काल प्रभाव से विधान परिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्देश दिया है।
एआईएमआईएम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मिर्जा रहमत बेग के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। पार्टी के संयुक्त सचिव एसए हुसैन अनवर की ओर से बेग को यह निर्देश जारी किया गया। हालांकि, पार्टी की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन कारणों या आरोपों के चलते उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है।
2023 में एमएलसी चुने गए थे बेग
मिर्जा रहमत बेग ने वर्ष 2023 में हैदराबाद लोकल अथॉरिटीज सीट से तेलंगाना विधान परिषद का चुनाव जीता था। चुनाव में जीत के बाद वह एआईएमआईएम के प्रतिनिधि के तौर पर विधान परिषद पहुंचे थे। पार्टी के मौजूदा फैसले के बाद अब उनके राजनीतिक भविष्य और विधान परिषद की सदस्यता को लेकर भी स्थिति पर नजर बनी हुई है।
इस्तीफे के निर्देश से बढ़ी सियासी हलचल
एआईएमआईएम की ओर से पार्टी से निष्कासन के साथ ही विधान परिषद के सभापति को इस्तीफा सौंपने का निर्देश दिए जाने से तेलंगाना की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ने अपने बयान में निष्कासन का कारण नहीं बताया है। ऐसे में कार्रवाई के पीछे की वजह को लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

अचानक चेन्नई सेंट्रल जेल पहुंचे सीएम विजय को देखने पहुंच गई भीड़

थाने में एसएचओ को बैठाकर की पूछताछ, औचक निरीक्षण से मचा हड़कंप

चेन्नई, एजेंसी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अचानक चेन्नई की पुझल सेंट्रल जेल और उसके बाद पुझल पुलिस स्टेशन पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस औचक दौरे से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को विजय के काफिले को देखने के लिए सड़क किनारे बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए। जेल के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सीधे एम-3 पुझल पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों से थाने के कामकाज और कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली।

पुझल सेंट्रल जेल देश के बड़े कारागार परिसरों में शामिल है। मुख्यमंत्री विजय ने यहां सबसे पहले महिला जेल परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों के वार्डों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कैदियों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं पर अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री विजय जेल की रसोई में भी पहुंचे और कैदियों के लिए तैयार किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई की जांच की। इसके बाद उन्होंने जेल अस्पताल, क्वारंटाइन क्षेत्र और नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं और कैदियों के स्वास्थ्य से जुड़े इंतजामों की जानकारी अधिकारियों से ली।
जेल परिसर में संचालित कक्षाओं और पुस्तकालय का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कैदियों के लिए पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में किताबें उपलब्ध कराई जाएं, ताकि उनमें पढ़ने की आदत विकसित हो। उन्होंने कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति भी देखी।
मुख्यमंत्री विजय ने जेल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से कड़े सवाल किए। उन्होंने रिश्वतखोरी, अवैध मोबाइल फोन के इस्तेमाल और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी ली। इसके अलावा हिरासत में होने वाली मौतों और कैदियों की आपसी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों की भी समीक्षा की। जेल के बाद मुख्यमंत्री पुझल पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से थाने की कार्यप्रणाली और इलाके में कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सब-इंस्पेक्टर कक्ष, कंप्यूटर रूम और लॉक-अप का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायत लेकर थाने पहुंचने वाले आम नागरिकों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिलें और उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कंप्यूटर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली तथा उनके रखरखाव की भी जांच की। मुख्यमंत्री के इस अचानक निरीक्षण को पुलिस और जेल प्रशासन की जवाबदेही परखने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

एनएएम शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रिजिजू

नई दिल्ली, एजेंसी।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) शिखर सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ के मौके पर सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 31 से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाली उच्चस्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक एनएएम के पहले राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखों के सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ का स्मरणोत्सव है। इस बैठक का मुख्य विषय गुटनिरपेक्षता की विरासत- आज की दुनिया के लिए सबक रखा गया है।
भारत, महत्वपूर्ण आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य है, और एनएएम के सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता रखता है। यह मंच दुनिया भर के 121 विकासशील देशों को एक साथ लाता है, जो साझा हितों और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ें 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग में हुए एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन में हैं, जहाँ संप्रभुता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और उपनिवेशवाद के विरोध जैसे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। औपचारिक रूप से यह आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में अस्तित्व में आया। आज भी, एनएएम बहुपक्षवाद को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने के लिए कार्यरत है।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारत ने एनएएम के विभिन्न मंचों पर आतंकवाद के साझा खतरे से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर लगातार जोर दिया है। पिछली एनएएम मंत्रिस्तरीय बैठकों में, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को गंभीर चुनौती बताया है, जिसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया गया है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने या उसका बचाव करने वाले किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शांति और सहयोग के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

बीजेपी सांसदों ने की सज्जन कुमार के परिजनों से मुलाकात, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगा दी फटकार

पणजी, एजेंसी।
नई दिल्ली,(ईएमएस)। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के 3 सांसदों को अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की कड़ी फटकार लगी है। यह फटकार 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में दोषी ठहराए गए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करने को लेकर लगी है। इसमें बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत, रामवीर सिंह बिधूड़ी और योगेंद्र चंदोलिया शामिल थे, जिन्होंने सज्जन कुमार के घर जाकर शोक जाहिर किया था।
सज्जन कुमार, जिनका 20 अगस्त को निधन हुआ, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के कई मामलों में दो उम्रकैद की सजा काट रहे थे। बीजेपी के तीनों सांसदों के कदम पर वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता एच.एस. फुल्का ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि वे तीनों सांसदों के दौरे की कड़ी निंदा करते हैं, और सज्जन कुमार को सामूहिक हत्यारा बताया। फुल्का ने सवाल उठाया कि बीजेपी, जिसने हमेशा दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई का समर्थन किया है, उसके सांसद एक दोषी के परिवार के प्रति सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं, जबकि सहानुभूति पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार, सांसदों के कदम की जानकारी पार्टी नेतृत्व को नहीं दी गई थी, इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने बेहद गंभीरता से लिया। शनिवार को उन्होंने इन तीनों सांसदों को तलब कर कड़ी फटकार लगाकर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह घटना तब हुई है जब पार्टी अपनी सार्वजनिक छवि और सिद्धांतों के प्रति अत्यंत सतर्क है। इस बीच, नवीन ने शनिवार को ही पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में युवाओं तक पार्टी की पहुंच बनाने की योजना और उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा गुजरात सहित सात राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।

सिंधु जलसंधि: पाकिस्तान की वैश्विक गुहार पर भारत का जबाव....खून और पानी साथ नहीं बह सकते

नई दिल्ली, एजेंसी।
सिंधु जलसंधि (आईडब्ल्यूटी) को लेकर पाकिस्तान इन दिनों ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुहम्मद इशाक डार ने हाल ही में भारत को चेतावनी दी है कि वह संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित पानी से वंचित करने का प्रयास न करे। हालांकि, भारत ने दो टूक कहा है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते और इस्लामाबाद भारतीय नागरिकों व सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर बिना किसी बदले की भावना के डेटा-शेयरिंग की उम्मीद नहीं कर सकता।
भारत सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि जल सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत का यह दो टूक जवाब डार के उन दावों के बाद आया है जिसमें उन्होंने आईडब्ल्यूटी को पूरी तरह से वैध, बाध्यकारी और लागू बताया था और संधि को स्थगित करने के भारत के कथित फैसले को खारिज कर दिया था। डार ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को पानी से वंचित करने के किसी भी प्रयास के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते है।
पाकिस्तानी उप-प्रधानमंत्री ने कहा कि 1960 में हस्ताक्षर होने के बाद से सिंधु जलसंधि को अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि यह संधि इसलिए कायम रही क्योंकि दोनों देशों को यह समझ थी कि करोड़ों लोगों का जीवन जिन जल स्त्रोतों पर निर्भर है, वे राजनीतिक उतार-चढ़ाव का शिकार नहीं बनाए जा सकते। डार ने जलवायु परिवर्तन का हवाला देकर बातचीत, पारदर्शी डेटा साझाकरण और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए जल सुरक्षा को आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और अंततः राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखेगा, तब तक पानी के मुद्दे पर सामान्य सहयोग की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह दर्शाता है कि भारत अब पानी के मुद्दे को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहा है और पाकिस्तान के वैश्विक दबाव के बावजूद अपने रुख पर कायम है।

प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना, किर्गिज भी जाएंगे

-व्यापार, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा, ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली, एजेंसी।
पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह उज्बेकिस्तान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के लिए रवाना होने से पहले लिखा- मैं 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज की यात्रा पर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में काफी प्रगति हुई है। मैं राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा, ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने और विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के हमारे साझा विजन को आगे बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं।
उन्होंने कहा कि मैं ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करूंगा, जो हमारे दोनों देशों को जोड़ने वाले गहरे सांस्कृतिक और लोगों के बीच के संबंधों का प्रतीक है। यह पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। यात्रा के दौरान पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

दिल्ली-एनसीआर की हवा सुधारने को पुराने ट्रक-बस निशाने पर

(लेंखक-विनोद सिंह तकियावाला)

9,585 करोड़ रुपये की परिवहन योजना में 2 लाख से अधिक वाहनों के प्रतिस्थापन का लक्ष्य,बैंक और ऑटो कंपनियां भी बनीं साझेदार

दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ करने की कोशिश में सरकार ने अब उन पहियों पर नजर डाली है,जो वर्षों से सड़कों पर दौड़ रहे हैं और जिनसे निकलने वाला धुआं हवा को लगातार जहरीला बना रहा है। प्रदूषण के कारणों की चर्चा जब भी होती है,वाहनों का नाम प्रमुखता से सामने आता है, लेकिन वाहनों की भी अपनी अलग-अलग श्रेणियां हैं।हर वाहन का प्रदूषण में योगदान एक जैसा नहीं है।खासकर पुराने ट्रक और बसें संख्या में कम होने के बावजूद प्रदूषण फैलाने में कहीं आगे हैं।इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने **PARIVARTAN** योजना शुरू की है।परियोजना का मकसद साफ है -पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों तथा बसों को सड़कों से हटाकर उनकी जगह **BS-VI** या उससे बेहतर उत्सर्जन मानक वाले अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों को लाया जाए।

सर्वविदित रहे कि विगत 3 जून 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी और 14 जुलाई को इसे शुरू किया गया। अब 27 अगस्त तक इसके पोर्टल पर 1,300 से अधिक लाभार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। योजना से 42 बैंक और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जुड़ चुकी हैं,जबकि 15 ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पात्र वाहन मालिकों को निर्धारित छूट देने के लिए समझौते किए हैं। शुरुआत भले ही छोटी दिखाई दे, लेकिन योजना का लक्ष्य काफी बड़ा है। सरकार दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हरियाणा,राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के जिलों में पंजीकृत दो लाख से अधिक पुराने ट्रकों और बसों को बदलना चाहती है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इनमें लगभग 1.91 लाख ट्रक और 16,329 बसें शामिल हैं।

यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली की हवा केवल दिल्ली की सीमा के भीतर नहीं बनती और न ही बिगड़ती है। राष्ट्रीय राजधानी में आने-जाने वाले भारी वाहन पूरे एनसीआर के परिवहन तंत्र का हिस्सा हैं। दिल्ली से बाहर का ट्रक भी दिल्ली की हवा में योगदान देता है और दिल्ली में चलने वाला ट्रक एनसीआर के किसी दूसरे शहर की हवा को प्रभावित करता है। इसलिए प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई भी प्रशासनिक सीमाओं से बाहर जाकर ही प्रभावी हो सकती है। **PARIVARTAN** का दायरा दिल्ली के साथ हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों तक रखना इसी सोच का हिस्सा है।योजना की जरूरत को समझने के लिए कुछ आंकड़े काफी हैं।सरकार द्वारा उद्धृत आकलनों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में परिवहन क्षेत्र का योगदान **PM**2.5 प्रदूषण में करीब 14 प्रतिशत, कार्बन मोनोऑक्साइड में 40 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड में लगभग 63 प्रतिशत है। लेकिन असली चिंता भारी वाहनों को लेकर है।ट्रक और बसें कुल वाहन बेड़े का लगभग तीन प्रतिशत हैं,लेकिन **PM**2.5 उत्सर्जन में उनकी हिस्सेदारी करीब 36 प्रतिशत बताई गई है। यानी सड़क पर उनकी संख्या कम है, मगर प्रदूषण में योगदान बहुत ज्यादा है। पुराने वाहनों के मामले में स्थिति और गंभीर है। सरकारी आकलन के मुताबिक एक प्री- **BS** भारी वाहन से होने वाला उत्सर्जन लगभग 14 **BS-VI** वाहनों के बराबर हो सकता है। **BS-IV** वाहन भी **BS-VI** वाहन की तुलना में करीब 2.7 गुना अधिक उत्सर्जन करता है। ऐसे में पुराने भारी वाहनों को हटाना प्रदूषण नियंत्रण की उस रणनीति का हिस्सा बन सकता है जिसमें कम संख्या में वाहनों को बदलकर अपेक्षाकृत बड़ा पर्यावरणीय लाभ हासिल किया जा सकता है। हालाँकि यहां यह समझना जरूरी है कि किसी ट्रक या बस मालिक के लिए उसका पुराना वाहन सिर्फ प्रदूषण फैलाने वाली मशीन नहीं है।वही उसकी पूंजी है,वही उसकी रोजी-रोटी है और उसी से उसके परिवार की आमदनी चलती है। ऐसे में केवल यह कह देना कि पुराना वाहन हटाइए, व्यवहारिक समाधान नहीं हो सकता। नया वाहन खरीदने के लिए बड़ी रकम चाहिए,बैंक से कर्ज लेना पड़ता है और कई वर्षों तक **EMI** चुकानी होती है। इसलिए यदि सरकार वास्तव में पुराने वाहनों को सड़क से हटाना चाहती है तो वाहन मालिक के सामने आर्थिक रूप से आकर्षक विकल्प रखना जरूरी है।

PARIVARTAN में इसी बात पर जोर दिया गया है। पात्रता वाले वाहन मालिक को नए वाहन के ऋण पर पाँच वर्षों तक पाँच प्रतिशत ब्याज बचत का लाभ मिलेगा।नए वाहन पर दस वर्षों के लिए रोड टैक्स की पूरी छूट और पंजीकरण शुल्क से भी राहत दी गई है।दिल्ली,हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारें इस संबंध मेंअधिसूचनाएं जारी कर चुकी हैं।इसके अलावा योजना में शामिल वाहन निर्माता एक्स-शोरूम कीमत पर कम से कम आठ प्रतिशत की छूट देंगे। यानी सरकार ने वाहन बदलने की लागत को अलग-अलग स्तरों पर कम करने की कोशिश की है।

ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन के मामले में भी योजना ने दोनों विकल्प खुले रखे हैं। **BS-VI** डीजल या ष्हहत्र वाहन खरीदने वालों को वाहन की श्रेणी के अनुसार पांच वर्षों तक हर महीने 1,200 रुपये से लेकर 4,800 रुपये तक के ईंधन वाउचर मिलेंगे।इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए 64,000 रुपये से लेकर 2.56 लाख रुपये तक का एकमुश्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार एक तरफ तत्काल उपलब्ध स्वच्छ तकनीक वाले **BS-VI** वाहनों को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर संक्रमण को भी प्रोत्साहित कर रही है।दिल्ली के मामले में कुछ श्रेणियों के लिए व्यवस्था और कड़ी है। **Light Goods Vehicles** के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता नहीं बल्कि अनिवार्यता दी गई है, जबकि बसों के लिए **BS-VI CNG** या इलेक्ट्रिक विकल्प रखा गया है। इससे साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए सरकार कुछ वाहन श्रेणियों में अपेक्षाकृत तेज बदलाव चाहती है,लेकिन पुराने वाहन को हटाना तभी प्रभावी होगा जब वह वास्तव में परिवहन व्यवस्था से बाहर हो। यदि पुराना ट्रक दिल्ली से हटकर किसी दूसरे शहर में चलने लगे तो प्रदूषण खत्म नहीं होगा,केवल उसकी जगह बदल जाएगी।इसीलिए योजना में स्क्रैपिंग को भी जोड़ा गया है। **BS-III** और उससे पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में स्क्रैप करना अनिवार्य है। **BS-IV** वाहनों के मामले में स्क्रैपिंग अथवा **NCR** से बाहरगैर-**NCAP** शहरों या कस्बों में बिक्री का विकल्प दिया गया है।इस व्यवस्था का उद्देश्य पुराने और अधिक प्रदूषणकारी वाहनों को धीरे-धीरे सड़क परिवहन व्यवस्था से बाहर करना है।इस पूरी योजना के लिए सरकार ने 9,585 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया है। इसमें 5,041 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की बजटीय सहायता है। योजना का वित्तपोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास है।इतनी बड़ी वित्तीय व्यवस्था बताती है कि सरकार इसे केवल प्रदूषण के मौसम में उठाया गया कोई तात्कालिक कदम नहीं मान रही, बल्कि इसे वाहन बेड़े के दीर्घकालिक बदलाव के रूप में देख रही है।इस बदलाव में बैंक और वाहन निर्माता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। 42 बैंक और **NBFC** के योजना से जुड़ने का अर्थ है कि वाहन मालिकों के लिए ऋण की व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर 15 ऑटो **OEM** का जुड़ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार अकेले नए वाहन खरीदने की लागत कम नहीं कर सकती। निर्माता की छूट और बैंक की वित्तीय सहायता मिलकर ही वाहन मालिक के लिए नया वाहन खरीदना व्यावहारिक बना सकती है।19 अगस्त को राजस्थान के अलवर में महेंद्र सिंह ने **PARIVARTAN** योजना के तहत पहला नया वाहन खरीदा।किसी योजना की पहली खरीद भले ही प्रतीकात्मक दिखाई दे,लेकिन वह इस बात का संकेत होती है कि सरकारी घोषणा अब वास्तविक लेन-देन में बदलने लगी है।अब इस एक उदाहरण को हजारों और फिर लाखों मामलों तक पहुंचाना योजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।क्योंकि 1,300 से अधिक पंजीकरण को अगर करीब 2.07 लाख संभावित लाभार्थियों के लक्ष्य के सामने रखकर देखा जाए तो अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। योजना की शुरुआत के स्तर पर यह संख्या उत्साहजनक हो सकती है, लेकिन अंतिम सफलता का पैमाना यह नहीं होगा कि कितने लोगों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया। असली सवाल यह होगा कि कितने पुराने ट्रक और बसें वास्तव में सड़क से हटे, कितने नए **BS-VI** और इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर आए और इससे दिल्ली-एनसीआर की हवा में कितना सुधार हुआ।इसके लिए जागरूकता भी जरूरी है और प्रक्रिया को आसान बनाना भी। सरकार ने पेट्रोल पंपों, ट्रांसपोर्ट नगरों, टोल प्लाजा और **RTO** कार्यालयों तक अभियान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल माध्यमों के जरिए वाहन मालिकों को योजना की जानकारी दी जा रही है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना का वास्तविक लाभ उसी समय मिलेगा जब वाहन मालिक को यह स्पष्ट समझ आएगा कि पुराना वाहन छोड़ने और नया वाहन खरीदने पर उसकी जेब पर कुल कितना असर पड़ेगा।**PARIVARTAN** की सफलता का एक दूसरा पहलू भी है। यह योजना केवल प्रदूषण नियंत्रण की कोशिश नहीं, बल्कि वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण का अवसर भी बन सकती है।नए वाहन अपेक्षाकृत बेहतर तकनीक वाले होंगे,ईंधन दक्षता बढ़ सकती है और परिवहन क्षेत्र धीरे-धीरे अधिक स्वच्छ तकनीक की ओर बढ़ सकता है। यदि इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव केवल उत्सर्जन तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता पर भी पड़ेगा। फिर भी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच की दूरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।दो लाख से अधिक वाहनों को बदलना आसान काम नहीं है। छोटे ट्रांसपोर्टरों की वित्तीय क्षमता, बैंक ऋण की शर्तें,नए वाहनों की उपलब्धता, स्क्रैपिंग की सुविधाएं और राज्यों के विभागों के बीच समन्वय -इन सभी मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा।यदि इनमें से किसी एक कड़ी में कमजोरी आई तो योजना की गति प्रभावित हो सकती है।दिल्ली-एनसीआर की प्रदूषण समस्या का समाधान निश्चित रूप से किसी एक योजना से नहीं होगा।पराली,धूल,निर्माण गतिविधियां,औद्योगिक प्रदूषण, मौसम और परिवहन -इन सभी पर समानांतर काम करना होगा। लेकिन जहाँ कुल वाहन बेड़े के करीब तीन प्रतिशत भारी वाहन **PM**2.5 उत्सर्जन में लगभग 36 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हों, वहां पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की पहल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता।

PARIVARTAN ने कम से कम दिशा स्पष्ट कर दी है।पुराने वाहन को केवल प्रतिबंधित करने के बजाय उसे बदलने का आर्थिक रास्ता दिया गया है। बैंक को साथ लिया गया है,वाहन निर्माता को साथ लिया गया है और राज्यों को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है।अब सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि इस व्यवस्था का लाभ कागज और पोर्टल से निकलकर वास्तविक वाहन मालिक तक पहुंचे।1,300 से अधिक पंजीकरण इस यात्रा की शुरुआत हैं। लक्ष्य करीब 2.07 लाख पुराने ट्रकों और बसों का है। इनके बीच का फासला बहुत बड़ा है,लेकिन यही फासला इस योजना की असली परीक्षा भी है।

संपादकीय

बिना हुनर के डिग्री

नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट हमारे नीति-नियंताओं को आईना दिखाने वाली है। चौंकाने वाली ये रिपोर्ट बताती है कि देश में नब्बे फीसदी से अधिक स्नातक ऐसी नौकरियां कर रहे हैं, जिसका उनकी डिग्री से कोई संबंध नहीं होता है। जाहिरा तौर पर यह आंकड़ा हमारी शिक्षा व्यवस्था की विसंगतियों को ही उजागर करता है। इसके मायने हैं कि आज भी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है ,जो मौजूदा आर्थिकी से नहीं जोड़ती। देश-दुनिया का मौजूदा आर्थिक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है। सरकारी नौकरियां ना के बराबर हैं, मगर हर स्नातक उसके लिये आवेदन करता है। जबकि रोजगार बाजार में उतरने के लिये युवाओं के पास कौशल विकास, व्यावहारिक दक्षता, तकनीकी ज्ञान और कुशल प्रबंधन का अनुभव होना जरूरी है। दरअसल, अधिकांश शिक्षण संस्थानों में आज भी वर्षों पुराना वह पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है जो मौजूदा प्रतिस्पर्धी समय में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी नहीं देता। इसके लिये जरूरी है कि युवाओं को उद्योग, बाजार व व्यावसायिक संस्थानों की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा दी जाए। लेकिन विडंबना यह है कि तीन-चार साल के अध्ययन के बाद छात्रों को जो डिग्री मिलती है, वह उन्हें रोजगार के बाजार में कदमताल करने का हुनर नहीं देती। यह तभी संभव है जब हमारी शिक्षा, कौशल विकास व अर्थव्यवस्था में तारतम्य स्थापित हो सकेगा। लेकिन हर साल लाखों बीए, एम.ए. व अन्य मानविकीय विषयों की डिग्री हासिल करने वाले बेरोजगारों की पंक्ति में शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि देश में स्नातक बेरोजगारों का प्रतिशत देश की सामान्य बेरोजगारी दर से कहीं अधिक है। महिला स्नातकों की दर तो पुरुष स्नातकों से भी कहीं ज्यादा है। ऐसे में उस उच्च शिक्षा का क्या औचित्य जो युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। असल में, बदलते वक्त के अनुरूप युवाओं की शिक्षा में जो जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए थे, वे अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाये हैं। दरअसल, हर युवा में कला-कौशल का एक विशिष्ट गुण होता है। उसका मूलभूत रुझान एक विशेष क्षेत्र में होता है। लेकिन इस गुण को न तो अभिभावक समझ पाते हैं और न ही शिक्षक। छात्र भेड़चाल में आकर शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेते हैं। लेकिन यह उनकी रुचि का विषय नहीं होता है। कई अध्ययन बताते हैं कि अपनी रुचि के विषय में युवा बेहतर कार्य प्रदर्शन करते हैं। यह संभव नहीं कि हर छात्र डॉक्टर व इंजीनियर ही बने। लेकिन समाज में ऐसा करने की होड़ बनी हुई है। एक समय बैंकिंग, रेलवे आदि में भविष्य तलाशने की होड़ लगी। पिछले कुछ समय में कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने का फैशन चला। वैश्विक स्थितियों में बदलाव व एआई के वर्चस्व के चलते अचानक कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में नौकरियों में तेजी से कटौती हुई। लेकिन देश में हजारों शिक्षण संस्थान आज भी इस भेड़चाल में युवाओं को धकेल रहे हैं। विडंबना यह है कि हमारे नीति-नियंताओं ने दूरदर्शी दृष्टिकोण न अपनाते हुए, भविष्य की दीवार पर लिखी इबारत को नहीं पढ़ा। यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश होने के बावजूद हम इस जनसांख्यिकीय लाभ उठाने में विफल रहे हैं। हमारे उद्योगों ने भी अपनी जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये इस बाबत चलाये जा रहे कार्यक्रमों में सहयोग नहीं किया। यही वजह है कि आज देश में कामचलाऊ इंटर्नशिप व अप्रेंटिसशिप का बोलबाला है। यदि हमारा निजी क्षेत्र इस दिशा में रचनात्मक पहल करता तो उसे बड़ी संख्या में अपनी जरूरतों के मुताबिक युवा प्रतिभाएं मिल सकती थीं।

नेपाल की बाढ़ और हमारी जल-दृष्टि

(लेखक-विवेक रंजन श्रीवास्तव)

बाढ़ को हम अक्सर प्रकृति का प्रकोप मानकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कई बार वह हमारे विकास मॉडल का आईना भी होती है। वह बताती है कि हमने नदी, पहाड़ और जल-प्रवाह की प्राकृतिक व्यवस्था को कितना समझा और उसे अपने अनुकूल मोड़ने की कितनी कोशिश की।

26 अगस्त 2026 को नेपाल-चीन सीमा के निकट आई भयावह आकस्मिक बाढ़ इसी बड़े प्रश्न को सामने लाती है। रासुवा जिले के तिमुरे और स्याफ्रुबेसी क्षेत्र से लेकर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी की घाटियों तक बर्फ, चट्टान, मलबे और पानी की प्रचंड धारा ने बस्तियों, पुलों, सड़कों और बिजली परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुँचाया। चीन के तिब्बत क्षेत्र का ग्यिरोंग भी प्रभावित हुआ। राहत और खोज अभियान जारी हैं तथा मृतकों और लापता लोगों के आँकड़े लगातार बदल रहे हैं।

यह सामान्य मानसूनी बाढ़ नहीं थी। प्रारंभिक वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार ऊँचाई पर हिमनद का हिस्सा और चट्टानें टूटकर नीचे गिरीं। उनसे निकला मलबा नदी में पहुँचा और जल-मलबे की अत्यंत शक्तिशाली धारा घाटी की ओर दौड़ पड़ी। इसलिए इसे केवल बाढ़ कहना पर्याप्त नहीं; यह हिमालय की अस्थिर होती भौगोलिक और जलवायवीय परिस्थितियों का संयुक्त संकेत है।

हिमनदों का पीछे हटना, नई हिमनद झीलों का बनना और उन्हें रोकने वाली बर्फ-मलबे की प्राकृतिक दीवारों का अस्थिर होना हिमालय के बढ़ते जोखिम हैं। ऐसी झील अचानक टूटे तो उसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जीएलओएफ कहते हैं। इस घटना को सीधे जीएलओएफ कहना अभी वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि बदलता हिमनद भूगोल हिमालयी आपदा-जोखिम को बढ़ा रहा है। नेपाल में खड़ी घाटियाँ, भूस्खलन, तीव्र मानसूनी वर्षा और भूकंपीय सक्रियता इस जोखिम को और जटिल बनाते हैं।

जलवायु परिवर्तन को इस आपदा का अकेला कारण मानना भी उतना ही अधूरा होगा। प्राकृतिक खतरा तब बड़ी आपदा बनता है जब उसके रास्ते में मनुष्य की बस्तियाँ और अवसंरचना खड़ी हो। प्रकृति खतरा पैदा करती है, लेकिन हमारी बसावट और निर्माण उसकी विनाशक क्षमता तय करते हैं। नेपाल के लिए यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलविद्युत उसकी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा व्यवस्था का प्रमुख आधार है। इस बाढ़ से अनेक जलविद्युत परियोजनाएँ, पारेषण लाइनें और अन्य ऊर्जा ढाँचे प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक आकलनों में लगभग 430 मेगावाट बिजली क्षमता पर असर बताया गया है। इससे सवाल उठता है , क्या पहाड़ी नदियों को केवल बिजली पैदा करने वाली मशीन के रूप में देखना उचित है?

नदी कोई स्थिर पाइपलाइन नहीं है। वह पानी के साथ गाद और चट्टानें लेकर चलती है, अपना पाट बदलती है, बाढ़ के मैदान बनाती है और अंततः समुद्र तक पहुँचती है। उसे बाँधकर या उसके प्राकृतिक जल-फैलाव क्षेत्र में निर्माण करके हम उसका व्यवहार बदल सकते हैं, उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं कर सकते। पानी को रास्ता चाहिए।

इसीलिए किसी एक परियोजना का अलग-अलग पर्यावरणीय आकलन पर्याप्त नहीं। जब एक ही नदी घाटी में सड़क, सुरंग, बाँध, जलविद्युत परियोजना, खनन, पर्यटन और बस्तियाँ विकसित हों तो पूरे नदी-बेसिन पर उनके सम्मिलित प्रभाव का अध्ययन जरूरी है। इसे क्यूम्युलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट अर्थात सम्मिलित प्रभाव आकलन कहा जाता है। भविष्य का पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रोजेक्ट-बाय-प्रोजेक्ट नहीं,बेसिन-बाय-बेसिन होना चाहिए। यहाँ चीन का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण वर्तमान बाढ़ को किसी चीनी बाँध के टूटने या पानी छोड़े जाने का परिणाम नहीं बताते। इसका तत्काल कारण प्राकृतिक हिमनद-चट्टान धंसाव और उससे बनी जल-मलबा धारा माना जा रहा है। लेकिन नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र में सड़क, व्यापार, पर्यटन और ऊर्जा से जुड़ी तेजी से बढ़ती अवसंरचना ने ऐसे संवेदनशील भूभाग में मानवीय और आर्थिक उपस्थिति बढ़ाई है। रासुवागढ़ी-केरुंग सीमा गलियारा इसका उदाहरण है। रासुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना में चीनी कंपनी की भागीदारी भी रही है।

इसलिए चीन को बाढ़ का कारण बताना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा, लेकिन चीन और नेपाल की सीमापार परियोजनाओं को आपदा-जोखिम के संदर्भ में देखने की आवश्यकता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। सवाल किसी एक देश की परियोजना का नहीं, हिमालयी भूगोल की वहन क्षमता का है।

बाँधों को भी इसी संतुलित दृष्टि से देखना चाहिए। वे सिंचाई, पेयजल, बिजली और बाढ़ नियंत्रण के उपयोगी साधन हैं, लेकिन अचूक समाधान नहीं। चीन का थ्री गॉर्जेस बाँध बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन का बड़ा उदाहरण है, वहीं विस्थापन, तलछट, जैव विविधता और नदी-तंत्र पर उसके प्रभावों ने गंभीर पर्यावरणीय बहस भी पैदा की है। बड़े जलाशयों के संदर्भ में जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है, लेकिन हर बाँध को भूकंप का कारण मानना उचित नहीं।

दुनिया में बाढ़ प्रबंधन की सोच भी बदल रही है। नीदरलैंड का रूम फॉर द रिवर कार्यक्रम नदी को हर हाल में बाँधने के बजाय उसे बाढ़ के समय फैलने के लिए सुरक्षित स्थान देने पर आधारित है। बांग्लादेश ने तटबंधों के साथ मैंग्रोव, जलनिकासी, चक्रवात आश्रय और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को जोड़ा है। संदेश स्पष्ट है,इंजीनियरिंग और पारिस्थितिकी एक-दूसरे के विकल्प नहीं, सहयोगी हो सकते हैं।

नेपाल और हिमालय के लिए भी समाधान केवल अधिक कंक्रीट नहीं है। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जंगल और आर्द्रभूमि बचाना, ढलानों को स्थिर रखना, बाढ़ के मैदानों को अतिक्रमण से मुक्त रखना, तलछट का वैज्ञानिक प्रबंधन, हिमनदों और झीलों की निरंतर निगरानी, उपग्रह आधारित पूर्व चेतावनी और स्थानीय समुदायों की तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

नेपाल की यह त्रासदी इसलिए केवल एक देश की आपदा नहीं, हमारी विकास-दृष्टि के सामने प्रश्न है। सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, सीमापार व्यापार चाहिए, जलविद्युत भी चाहिए। लेकिन विकास का अर्थ प्रकृति को परास्त करना नहीं हो सकता। हमें पहाड़ की वहन क्षमता, नदी के स्वभाव और बदलती जलवायु, तीनों को साथ साथ पढ़ना होगा।

हमने नदियों को सदियों तक माता कहा, फिर आधुनिक विकास में उन्हें पानी की पाइपलाइन, बिजली की टरबाइन और निर्माण-स्थल समझ लिया। अब समय है कि नदी को फिर एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र की तरह देखा जाए।

नदी को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, उसका रास्ता बदला जा सकता है, उसकी प्रकृति नहीं बदली जा सकती।

कर्त्तव्य को बनाएं सर्वोपरि लक्ष्य

अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा- 'रामायण और महाभारत में क्या अंतर है?' विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए। अध्यापक को संतोष नहीं हुआ। एक विद्यार्थी ने अनुरोध किया- 'आप ही बताइए' अध्यापक बोला-रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर है 'हक-हकूक' का। रामायण में राम ने अपना अधिकार छोड़ा, राज्य छोड़ा और चौदह वर्षों तक वन में जाकर रहे। वे चाहते तो अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते थे। दशरथ उन्हें वन में नहीं भेजना चाहते थे। अयोध्या की जनता उनके वन-गमन से व्यथित थी। पर राम ने अपने कर्त्तव्य को अधिकार से ऊपर रखा। पिता के कहे का पालन उनके जीवन का महान आदर्श था।

महाभारत का संपूर्ण कथानक अधिकारों की लड़ाई का कथानक है। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। भाई-भाई के रिश्तों में जो गंध होती है, मिठास होती है, अपनापा होता है, उसका दर्शन ही वहां कहां होता है! पांडव सब कुछ जुए में हार गए। सब वादे पूरे कर वे लौटे तो दुर्योधन ने पांच गांव तो क्या, सूई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर दिया।

ये दो उदाहरण हैं - हमारे सामने। प्रथम उदाहरण अपनेपन से भरे आत्मीय संबंधों का है। यह संबंधों की मधुरता व्यक्ति को कभी आत्मकेंद्रित नहीं होने देती। वह अपने बारे में नहीं सोचता; परिवार, समाज और देश के बारे में सोचता है। उसका अपना कोई स्वार्थ होता ही नहीं। पद-प्रतिष्ठा और सुख-सुविधा के संस्कारों से वह ऊपर उठ जाता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है, जो कर्त्तव्य को अपने जीवन का सवरेपरि लक्ष्य मानता है। वह संस्कृति सफल होती है जो कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को जन्म देती है।

वह शताब्दी सफल होती है, जो कर्त्तव्य की धारा को सतत प्रवाही बनाकर जन-जन तक पहुंचाती है। वह परंपरा सफल होती है, जो कर्त्तव्य का बोध देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और सुख-सुविधा की अर्थहीन चिंता छोड़कर व्यक्ति अपने जीवन को कर्त्तव्य के लिए समर्पित कर दे।

विचार मंथन

कानून पढ़ने वाले छात्रों के निशाने पर मुख्य न्यायाधीश?

(लेखक - सनत जैन)

भारत में न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से देश की जनता केवल कानूनी फैसलों की अपेक्षा नहीं करती, बल्कि निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों की रक्षा की उम्मीद भी करती है। ऐसे में जब देश के प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी ही मुख्य न्यायाधीश की भूमिका और सार्वजनिक आचरण पर सवाल उठाने लगें, तब इसे केवल एक व्यक्ति के विरोध के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। यह विरोध न्यायपालिका और नई पीढ़ी के बीच पैदा हो रहे विश्वास के संकट का सबसे बड़ा संकेत है। इसी तरह से आम जनता के लिए अलग, सरकार और बड़े-बड़े लोगों के लिए न्यायपालिका की अलग भूमिका को लेकर पिछले कुछ वर्षों में यह विरोध बढ़ता हुआ दिख रहा है। आम लोगों के दिमाग में यह बात घर कर रही है, कि इस देश में दो तरह के कानून लागू हैं। एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। हाल के घटनाक्रम ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। हैदराबाद स्थित नल्सर यूनिवर्सिटी के सैकड़ों विद्यार्थियों ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आपत्ति जताई। विद्यार्थियों ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई से संबंधित मामले की सुनवाई में वीडियो देखने से इनकार किए जाने को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद बेंगलुरु की प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) में भी विद्यार्थियों और पूर्व विद्यार्थियों ने मुख्य न्यायाधीश तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की प्रस्तावित उपस्थिति पर आपत्ति दर्ज कराई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 165 स्नातक विद्यार्थियों, 409 वर्तमान विद्यार्थियों और 128 पूर्व विद्यार्थियों ने इस संबंध में खुला पत्र जारी कर अपना विरोध दर्ज कराया। अंततः 2026 का दीक्षांत समारोह रद्द कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को डिग्रियां डाक से भेजना और स्वयं छात्रों को प्रदान करना शुरू कर दिया। यह घटना इसलिए असाधारण है, क्योंकि कानून के विद्यार्थी न्यायपालिका से बाहर के नहीं हैं। उन्हें लंबे समय तक कानून की पढ़ाई कर संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संवैधानिक संस्थाओं व लोकतंत्र के बारे में ज्ञान अर्जित किया है। यह छात्र न्याय प्रक्रिया को समझने वाले वर्ग के हैं। वे संविधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता का ज्ञान हासिल किया है। यदि यही विद्यार्थी शांतिपूर्ण और संस्थागत तरीके से किसी न्यायिक पदाधिकारी के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं, तो लोकतंत्र में इसे सुनना चाहिए, मनन कुमार मिश्रा ने बार काउंसिल की ओर से विरोध को दबाने का जो प्रयास किया था, उनका भी इन छात्रों ने विरोध किया।

मुख्य न्यायाधीश की 'कॉकरोच' टिप्पणी पर भी युवाओं के बीच व्यापक प्रतिक्रिया हुई है। मई में एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से की थी, जो कानून के पेशे में रोजगार न मिलने के बाद मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई गतिविधियों के माध्यम से व्यवस्था पर हमला करते हैं। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया, कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री के आधार पर पेशे में आने वाले लोगों के संदर्भ में थी, समूचे भारतीय युवाओं के लिए नहीं। मुख्य न्यायाधीश के इन शब्दों का लोकतंत्र में प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना शब्दों का उद्देश्य। युवाओं ने उस टिप्पणी को जिस तरह ग्रहण किया, वह अपने आप में बदलाव का एक बड़ा संकेत है। इसी प्रतिक्रिया से 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसा व्यंग्यात्मक युवा आंदोलन भी देश में उभरा। अब यह देश भर में बड़ी तेजी के साथ फैल गया है। युवा पीढ़ी अपने अधिकारों को लेकर सजग हुई है। सबसे बड़ा सवाल मुख्य न्यायाधीश के विरोध का नहीं है, सवाल यह है क्या, न्यायपालिका के प्रति असहमति व्यक्त करने की लोकतांत्रिक जगह बची रहेगी? यदि कानून के कॉलेज के छात्रों के बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और बार काउंसिल के किसी निर्णय, टिप्पणी या प्रक्रिया से असहमत हैं, ऐसी स्थिति में असहमति का जवाब तर्क, संवाद और संविधान के दायरे में होना चाहिए। न्यायपालिका को भी यह समझना होगा, आज की जेन-जी और आने वाली जेन-अल्फा पीढ़ी प्रश्न पूछती है। वीडियो रिकॉर्ड करती है, दस्तावेज मांगती है। संस्थाओं और जिन व्यक्तियों के पास अधिकार हैं। उनसे जवाबदेही भी चाहती है। मुख्य न्यायाधीश देश के सबसे शक्तिशाली संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उनके प्रति सम्मान आवश्यक है। लोकतंत्र में सम्मान और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र में दोनों साथ-साथ चलते हैं। आज की सबसे बड़ी चिंता यह नहीं होनी चाहिए कि कुछ विद्यार्थियों ने मुख्य न्यायाधीश का विरोध क्यों किया, चिंता यह होनी चाहिए कि कानून पढ़ने वाली नई पीढ़ी न्यायपालिका से संवाद के बजाय टकराव क्यों महसूस कर रही है। यदि इस दूरी को समय रहते संवाद से नहीं भरा गया, तो यह केवल एक दीक्षांत समारोह का विवाद नहीं रहेगा। यह आने वाली पीढ़ी और संविधान की सर्वोच्च व्याख्याकार संस्था के बीच विश्वास का प्रश्न बन सकता है। इसलिए आज आवश्यकता किसी पक्ष की जीत की नहीं, बल्कि न्यायपालिका की गरिमा, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान में जनता के विश्वास की रक्षा करने की है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

डिबॉक इंडस्ट्रीज और एमडी पर 7 साल का प्रतिबंध

मुंबई ।

शेयर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने डिबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक पर बड़ी कार्रवाई की है। कथित अकाउंटिंग फ्रॉड और वित्तीय आंकड़ों में हेरफेर के आरोप में दोनों को 7 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही, सेबी ने 59.30 करोड़ रुपये की अवैध कमाई जब्त करने और राइट्स इश्यू से डायवर्ट किए गए 49 करोड़ रुपये 12 फीसदी ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। सेबी के अनुसार, कंपनी ने फर्जी बिक्री, खरीद और सर्कुलर लेनदेन के जरिए वित्तीय आंकड़ों को बढ़ाया, जिससे करीब 4.21 करोड़ शेयर फर्जी तरीके से हासिल कर निवेशकों को बेच दिए गए। प्रबंधक मुकेश सिंह पर अकेले 20.10 करोड़ रुपये सहित कुल 29 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

सुनील कलोट को पांच साल जबकि प्रियंका शर्मा और गौरव जैन को तीन साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित किया गया है। एक अन्य मामले में, सेबी ने ट्रैफिकसोल आईटीएस टेक्नोलॉजिज और उसके प्रमोटर-निदेशकों जितेंद्र दास व पूनम दास पर एक साल का प्रतिबंध और 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जियो प्लेटफॉर्म्स के मेगा आईपीओ को मिली सेबी की हरी झंडी

मुंबई ।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स को बाजार नियामक सेबी से अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। यह आईपीओ करीब 37,000 करोड़ रुपये का हो सकता है, जो भारतीय शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बनने को तैयार है। सेबी ने जून में जमा कराए गए ड्राफ्ट दस्तावेजों के लगभग दो महीने बाद अपनी अंतिम टिप्पणियाँ दीं। निवेशकों को लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार था। यह प्रस्तावित इश्यू हुंडई मोटर्स इं डिया के 27,870 करोड़ रुपये के आईपीओ का रिकॉर्ड तोड़ेगा, जो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पब्लिक ऑफरिंग है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने 27 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) का कोई हिस्सा नहीं है, यानी मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। हालांकि, इश्यू का अंतिम आकार लॉन्च के समय इसके स्ट्रक्चर और प्राइसिंग पर निर्भर करेगा।

टाटा संस को राहत, एजीएम के लिए साल के अंत तक का समय

कंपनी रजिस्ट्रार ने तीन महीने की मोहलत दी

नई दिल्ली ।

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए बड़ी राहत मिली है। कोरम पूरा न होने के कारण पहले स्थगित हुई एजीएम के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) ने अब तीन महीने की मोहलत दे दी है, जिससे कंपनी के पास 31 दिसंबर तक का समय है। यह निर्णय सर रतन टाटा ट्रस्ट (एसआरटीटी) पर लगी रोक के कारण पैदा हुई असाधारण स्थिति और टाटा संस के नेतृत्व में अनिश्चितता को देखते हुए लिया गया है। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय ने 27 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से यह मोहलत दी है। इससे पहले, कंपनी कानून के तहत एजीएम के लिए निर्धारित समय-सीमा 30 सितंबर थी। एजीएम के एजेंडे में चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार का मामला भी शामिल था, जिस पर पहली बैठक में चर्चा नहीं हो पाई थी। दरअसल, 18 अगस्त को होने वाली एजीएम को इसलिए टालना पड़ा था क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स की अहम हिस्सेदार सर रतन टाटा ट्रस्ट पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर ने रोक लगा दी थी। सर रतन टाटा ट्रस्ट की टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और इस रोक के कारण एजीएम में अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं हो पाई। टाटा समूह के 100 साल से अधिक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि उसकी होल्डिंग कंपनी की एजीएम स्थगित करनी पड़ी हो। चैरिटी कमिश्नर का यह आदेश महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट में हुए बदलाव के कथित उल्लंघन पर आया था। इस बदलाव के तहत ट्रस्ट के बोर्ड में हमेशा बने रहने वाले ट्रस्टियों (परपेचुअल ट्रस्टी) की संख्या कुल सदस्यों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। टाटा संस ने इसी असाधारण स्थिति का हवाला देते हुए मोहलत की अपील की थी। हालांकि, कंपनी रजिस्ट्रार ने मोहलत देते हुए टाटा संस को भविष्य में कंपनी अधिनियम के तहत सभी आवश्यक नियमों के अनुपालन में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी है।

भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव भरा रहा सप्ताह

ईरान प्रतिबंध, तेल कीमतें और वैश्विक संकेतों ने तय की बाजार की चाल

मुंबई।

बीता सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा, जहां प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार अस्थिरता के शिकार हुए। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों, कच्चे तेल की कीमतों में घट-बढ़ और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते बाजार ने हर दिन नई चाल चली। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को तेजी के साथ हुई, जब तेल कीमतों में गिरावट के कारण सेंसेक्स 77,748 और निफ्टी 24,302 के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, दिन का अंत निराशाजनक रहा और मुनाफावसूली ने बाजार को नीचे धकेल दिया, जिससे सेंसेक्स 77,369 पर और निफ्टी 24,219 पर बंद हुए। मंगलवार को भी बाजार लाल निशान पर खुला, लेकिन अंतिम समय की खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट ने सूचकांकों को बढ़त दिलाई, और सेंसेक्स 77,656, जबकि निफ्टी 24,334 पर बंद हुए। बुधवार को भी बाजार में ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला। कच्चे तेल में नरमी और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन पर ईरान-ओमान वार्ता से मिली उम्मीदों के बावजूद, बाजार सकारात्मक शुरुआत के बाद अंततः गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 77,472 और निफ्टी 24,207 पर सिमट गए। सप्ताह का सबसे चुनौतीपूर्ण दिन गुरुवार रहा, जब वीकली और मासिक एक्सपायरी के चलते भारी बिकवाली देखी गई। बाजार ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और सेंसेक्स 539 अंक गिरकर 76,934 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी भी 24,091 के नीचे आ गया। प्रमुख शेयरों जैसे हिन्दालको और महिंद्रा एंड महिंद्रा में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, दो दिनों की लगातार गिरावट के बाद शुक्रवार को बाजार ने कुछ राहत की सांस ली। सकारात्मक शुरुआत हुई और आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया। सेंसेक्स 330.92 अंक चढ़कर 77,264.51 पर, जबकि निफ्टी 84.80 अंक बढ़कर 24,175.65 पर बंद हुआ। निफ्टी आईटी सूचकांक में 3.51 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई, जिससे बाजार में सकारात्मक माहौल बना। कुल मिलाकर यह सप्ताह भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और घरेलू मुनाफावसूली के प्रभाव में रहा।

पुणे स्थित वेयरहाउस का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द

भंडारण, पैकेजिंग और भ्रामक लेबलिंग में मिली गंभीर खामियां

मुंबई ।

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड की पुणे स्थित कैरी एंड फॉरवर्डिंग (सीएंडएफ) इकाई का दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई वाडकी, पुणे जिले के गोदाम में भंडारण, पैकेजिंग और वापस मंगाने की प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं के मद्देनजर की गई है। एफडीए ने बताया कि लाइसेंस रद्द करने का आदेश 27 अगस्त से प्रभावी हो गया है, जिसे कंपनी ने अदालत में चुनौती दी है। नियामक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोदाम में दवाएं सीधे फर्श पर रखी मिलीं और एक्सपायर्ड दवाओं के प्रबंधन में भी गंभीर कमियां पाई गईं। जून में हुए निरीक्षण में अधिकारियों ने डॉक्टर के पर्चे पर बिकने वाली दवा रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स की पैकेजिंग पर इसे अनधिकृत रूप से एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक बताते हुए पाया था। एफडीए ने इस भ्रामक लेबलिंग के चलते 11.19 लाख रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया था, जिसे औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 का उल्लंघन बताया गया। एफडीए ने कंपनी को गलत लेबल वाली रिएक्टिन प्लस टैबलेट्स को बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया था, लेकिन नियामक के अनुसार कंपनी ने इन निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया। बाद के निरीक्षणों में सीएंडएफ इकाई की दवा बिक्री एवं वितरण व्यवस्था में भंडारण संबंधी कमियां, खरीद-बिक्री रिकॉर्ड और वास्तविक कंप्यूटरीकृत स्टॉक के आंकड़ों में विसंगतियां भी सामने आईं, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया है।

सेबी ने ईटीएफ नियमों के क्रियान्वयन की समयसीमा बढ़ाई

अब 7 सितंबर से प्रभावी होंगे नए प्रावधान

नई दिल्ली ।

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के क्रियान्वयन की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है, जो अब 1 सितंबर 2026 के बजाय 7 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगे। यह निर्णय शेयर बाजारों से मिले सुझावों और नियमों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सेबी द्वारा जारी एक नए परिपत्र के अनुसार यह विस्तार ईटीएफ के आधार मूल्य, मूल्य दायरे, प्री-ओपन सत्र में कॉल नीलामी और क्लोज-आउट प्रक्रिया जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़े नियमों पर लागू होगा। इन प्रावधानों को नियामक ने 15 जून 2026 को जारी एक पिछले परिपत्र में विस्तृत रूप से तय किया था।

हालांकि, 15 जून के उस परिपत्र के अन्य सभी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। नियामक ने बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) को इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रणालियां तैयार करने, संबंधित उपनियमों में संशोधन करने और निवेशकों सहित सभी बाजार प्रतिभागियों को इन प्रावधानों के बारे में सूचित करने के निर्देश दिए हैं।

केंद्रीय मंत्री ओराम का हाथ काटने की क्षमता, बयान पर मच गया बवाल

नई दिल्ली ।

केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुएल ओराम ने अपनी ही पार्टी के सहयोगियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटवाने और उनकी राजनीतिक साख को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनके विस्फोटक बयान ने ओडिशा की राजनीति में खलबली पैदा कर दी है।

यह विवाद तब गरमा गया जब ओराम के करीबी सहयोगी राकेश पासवान को ओडिशा के राउरकेला में संगठित अपराध मामले में गिरफ्तार किया। आरोम के करीबी पासवान पर सरकारी गेस्ट हाउस में अपराधियों को पनाह देने का आरोप है। शुरुआत में ओराम ने कानून को अपना काम करने देने की बात कही थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने विरोधी गुट पर निशाना साधकर कहा कि पार्टी के कुछ नेता पैसा बहाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सुंदरगढ़ से छह बार सांसद रह चुके ओराम ने घोषणा की कि इस राजनीतिक साजिश के बाद उन्होंने 2029 का लोकसभा चुनाव न लड़ने का अपना फैसला बदला है और वे निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि वे दुष्प्रचार के पीछे के लोगों का पता लगाएंगे और इसकी शिकायत ओडिशा भाजपा के संगठन महामंत्री से भी की है। इस दौरान उन्होंने एक बेहद विवादित बयान देकर चेतावनी दी कि जो लोग उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाथ काटने की क्षमता उनमें है। केंद्रीय मंत्री ओराम के तीखे बयान से राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल और कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा को घेरना शुरू किया है। बीजेडी नेता प्रमिला मलिक ने भाजपा के भीतर गहरे अंदरूनी मतभेद का संकेत बताया, जबकि ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने ओराम की भाषा को असंसदीय और हिंसक बताकर भारतीय लोकतंत्र में ऐसी बयानबाजी के लिए कोई जगह न होने की बात कही।

इंडिगो वेंचर्स का एआई कंपनी सर्वम में रणनीतिक निवेश, परिचालन दक्षता पर जोर

सीरीज-बी फंडिंग के तहत हुई साझेदारी; यह वेंचर का चौथा सार्वजनिक निवेश

नई दिल्ली

विमानन दिग्गज इंडिगो की कॉरपोरेट वेंचर कैपिटल इकाई इंडिगो वेंचर्स ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) कंपनी सर्वम में रणनीतिक निवेश की घोषणा की है। सीरीज-बी फंडिंग के तहत यह कदम विमानन परिचालन में एआई अनुप्रयोगों से दक्षता व ग्राहक अनुभव सुधारने के लिए उठाया गया है। हालांकि, निवेश राशि का खुलासा नहीं किया गया है। इंडिगो और सर्वम पहले से ही ग्राहक सेवा, कर्मचारियों की उत्पादकता और विमानन संचालन से जुड़े एआई ऐप्लिकेशन पर सहयोग कर रही हैं। इस निवेश के बाद दोनों कंपनियां इन ऐप्लिकेशन्स के विकास और परीक्षण जारी रखेंगी।

सफल साबित होने वाले एआई समाधानों को इंडिगो के पूरे नेटवर्क में लागू किया जा सकता है, जिससे कंपनी के संचालन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। यह इंडिगो वेंचर्स का सार्वजनिक रूप से घोषित चौथा निवेश है, जो प्रौद्योगिकी और विमानन के भविष्य में उसके बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

इससे पहले, वेंचर ने जुलाई 2025 में एरोस्पेस विनिर्माण कंपनी जेह एरोस्पेस में निवेश किया था।

दिल्ली में सीएनजी 3.89 रुपए महंगी, 86.98 रुपए किलो पहुंची

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने जारी की नई दरें

नई दिल्ली ।

मध्य पूर्व में जारी भू-राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की बढ़ती कीमतों के बीच दिल्ली-एनसीआर के उपभोक्ताओं पर एक और महंगाई का बोझ पड़ा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने सीएनजी की कीमतों में 3.89 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि शनिवार सुबह से प्रभावी हो गई है, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी 86.98 रुपये प्रति किलोग्राम पर मिलेगी। यह इस वर्ष सीएनजी की कीमतों में पांचवीं वृद्धि है। मई के बाद यह पहला मौका है जब दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। मई माह में भी महज 10 दिनों के भीतर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने 6 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने अपने बयान में बताया कि वैश्विक बाजार में एलएनजी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, जिसके कारण उनकी खरीद लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। भारत को युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अधिक कीमत पर एलएनजी आयात करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर दिख रहा है।

31 को 8वें वेतन आयोग की अहम बैठक, कर्मचारी-संगठन रखेंगे सिफारिशे व सुझाव

फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन, पेंशन सुधार जैसे मुद्दों पर अंतिम फैसला लेगी सरकार

नई दिल्ली, ।

8वें वेतन आयोग के गठन को 10 महीने होने वाले हैं। वेतन आयोग जयपुर में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली अपनी अगली बैठक की तैयारी कर रहा है। इस बैठक के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त थी। इस बैठक में राजस्थान के केंद्रीय कर्मचारी या संगठन अपनी सिफारिशों या सुझाव को वेतन आयोग के सामने रख सकेंगे। इसके बाद वेतन आयोग सुझाव को अपनी सिफारिशों में रखेगा और सरकार को सौंपेगा। इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन, पेंशन सुधार, भत्ते और अन्य संबंधित मुद्दों पर अंतिम फैसला लेगी।8वां वेतन आयोग चर्चा और सलाह-मशविरा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आयोग का मकसद चर्चा की प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना है ताकि ज्याद से ज्यादा यूनियन, स्टेकहोल्डर और एसोसिएशन अपनी राय और शिकायतें रख सकें। पिछले कुछ महीनों में, 8वें वेतन आयोग ने दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया है। ये बैठकें अहम हैं क्योंकि देश भर की यूनियनों और स्टेकहोल्डर्स द्वारा इनमें रखी गई शिकायतें, अनुरोध और राय 8वें वेतन आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगी।3 सितंबर को वेतन आयोग के गठन को दस महीने पूरे हो जाएंगे। वेतन आयोग को नवंबर 2025 में अपने गठन के बाद से केंद्रीय मंत्रिमंडल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था। ऐसे में आयोग द्वारा मई-जून 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है।

इसके बाद सरकार सिफारिशों को लागू करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार एक जनवरी 2026 से ये सिफारिशें लागू कर सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि सरकार अक्षरशः इन सिफारिशों को लागू करे।

इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यह सरकार को तय करना होता है।छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान काफी विचार-विमर्श के बाद क्रमशः 1.86 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनी थी। अब यह देखना होगा कि 8वें वेतन आयोग के लिए क्या फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है क्योंकि एनसी (जेसीएम) और बीपीएमएस जैसी कई प्रमुख यूनियनें 3.5 गुना से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं।

जीएमआर का वैश्विक उड़ान लक्ष्य, भारतीय विमानन पर अटूट विश्वास

समूह पश्चिम एशिया, यूरोप व दक्षिण-पूर्व एशिया में तलाशेगा नए अवसर

नई दिल्ली

जीएमआर समूह ने भारतीय विमानन क्षेत्र में दीर्घकालिक वृद्धि पर अपने प्रबल विश्वास को व्यक्त करते हुए वैश्विक विस्तार की महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। समूह पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में हवाई अड्डों तथा उनसे जुड़े कारोबार में नए अवसर तलाशेगा। कंपनी के एक अे धिकारी ने कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में इन रणनीतिक पहलों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि जीएमआर वर्तमान में भारत में छह हवाई अड्डों (दिल्ली और हैदराबाद सहित) तथा इंडोनेशिया में एक हवाई अड्डे का संचालन करता है, जबकि यूनान में एक का विकास जारी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के भोगापुरम हवाई अड्डे ने 17 अगस्त से परिचालन शुरू किया है। राव ने बढ़ती आय, पर्यटन, मजबूत बुनियादी ढांचे और सरकारी पहलों से भारतीय विमानन को दीर्घकालिक समर्थन मिलने पर जोर दिया। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कंपनी ने अपने एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म कारोबार का विस्तार किया है, जिसमें शुल्क-मुक्त, मालवाहक, खुदरा और खाद्य-पेय जैसे कम पूंजी वाले व्यवसाय शामिल हैं। समूह नई रियायतों, परिचालन एवं रखरखाव अनुबंधों तथा हवाई अड्डों से जुड़े कम पूंजी वाले क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाएगा। पिछले वित्त वर्ष में, जीएमआर हवाई अड्डों से 11.46 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की, जो देश के कुल घरेलू हवाई यातायात का लगभग 25.6 फीसदी और अंतरराष्ट्रीय यातायात का 33.9 फीसदी था।

जियो समेत चार कंपनियों को आईपीओ लाने के लिए सेबी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली।

इस हफ्ते सिर्फ जियो ही नहीं पेट लिमिटेड, सद्भाव फ्यूचरटेक लिमिटेड, पारस हेल्थकेयर लिमिटेड और एमके संस फाइन ज्वेल्स लिमिटेड को आईपीओ लाने के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी है यानी आने वाले समय में आईपीओ की बहार आएगी। बाजार नियामक सेबी की जानकारी के मुताबिक इन चारों कंपनियों ने मार्च से जून के बीच आईपीओ के लिए मसौदा दस्तावेज दाखिल किए थे और 24 से 28 अगस्त में उन्हें सेबी की अंतिम टिप्पणियां मिलीं। सेबी की टिप्पणियां आईपीओ प्रक्रिया में एक अहम कदम होती हैं। इसके बाद कंपनियां लागू नियामकीय जरुरतों के आईपीओ की आगे की तैयारियां कर सकती हैं।

भारत पेट ने 25 मार्च को सेबी के पास आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 26 अगस्त को नियामक की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ का आकार करीब 760 करोड़ रुपए है। इसमें 120 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवर्तक करीब 640 करोड़ रुपए के शेयर बिक्री पेशकश के तहत बेचेंगे। सद्भाव फ्यूचरटेक ने सात अप्रैल को आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 28 अगस्त को सेबी की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 2.55 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी करने के साथ प्रवर्तकों और अन्य शेयरधारकों की ओर से कुल 235 करोड़ की बिक्री पेशकश शामिल है।

पारस हेल्थकेयर ने 16 जून को आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 24 अगस्त को सेबी की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी आईपीओ के जरिए 1,800 करोड़ तक जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 500 करोड़ रुपए तक के नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि बिक्री करने वाला शेयरधारक 1,300 करोड़ रुपए तक के शेयर बिक्री पेशकश के तहत बेचेगा। कंपनी आईपीओ से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कुछ बकाया कर्ज के समय से पहले या निर्धारित पुनर्भुगतान, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी पीएमएचपीएल में उसके कर्ज के पुनर्भुगतान या समय से पहले भुगतान और सामान्य कंपनी कामकाज के लिए करेगी।

पारस हेल्थ ब्रांड के तहत परिचालन करने वाली कंपनी के पास 31 मार्च, 2026 तक आठ अस्पताल थे। इसकी कुल क्षमता 2,211 बिस्तरों की है। एमके संस फाइन ज्वेल्स ने 14 मई को आईपीओ के दस्तावेज दाखिल किए थे और उसे 28 अगस्त को सेबी की टिप्पणियां मिलीं। कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ में 1.36 करोड़ तक नए इक्विटी शेयर जारी किए। इसके अलावा प्रमोटर रामचंद मुरलीधर रैमलानी 34 लाख तक शेयर बिक्री पेशकश के तहत बेचेंगे।

वीआई ने लगातार चौथे महीने जोड़े नए ग्राहक, 20 करोड़ पहुंचा आंकड़ा

ट्राई के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में 2.4 लाख से अधिक उपभोक्ता जुड़े

नई दिल्ली ।

दूरसंचार क्षेत्र में अपनी वापसी का संकेत देते हुए निजी क्षेत्र की कंपनी वोडाफोन आइडिया (वीआई) लगातार चौथे महीने नए ग्राहक जोड़ने में सफल रही है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह कंपनी के लिए एक सकारात्मक मोड़ है, खासकर वर्षों की ग्राहक हानि के बाद। जुलाई में 2,40,114 नए ग्राहक जुड़ने से कंपनी की कुल ग्राहक संख्या 19.90 करोड़ हो गई है, जो 20 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब है। यह उपलब्धि वीआई के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि 2018 में विलय के बाद कंपनी ने पहली बार किसी तिमाही (अप्रैल-जून वित्त वर्ष 2027) में शुद्ध नए ग्राहक जोड़े हैं। फरवरी से अब तक कंपनी ने 6.9 लाख से अधिक और अप्रैल से 5.7 लाख से अधिक ग्राहक अपने साथ जोड़े हैं।

यह पिछले साल के उस दौर से बिल्कुल अलग है, जब कंपनी ने छह महीनों में 36 लाख से अधिक ग्राहक खो दिए थे। आदित्य बिड़ला ग्रुप के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने इसे एक अहम पड़ाव बताते हुए नेटवर्क ढांचे और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने में किए गए निरंतर निवेश का परिणाम बताया है। मुख्य कार्यकारी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले एक वर्ष में 15,500 और दो वर्षों में 32,000 4जी मोबाइल टावर एवं उपकरण लगाने से नेटवर्क में सुधार हुआ है, जिससे ग्राहकों की संतुष्टि और उन्हें बनाए रखने की क्षमता बढ़ी है।

किशोर के अनुसार, जिन क्षेत्रों में 5जी सेवा शुरू हुई है, वहां ग्राहकों के जुड़ाव में स्पष्ट सुधार देखा जा रहा है। वीआई ने पिछले वर्ष मार्च में दिल्ली से अपनी 5जी सेवा शुरू की थी और अगले दो तिमाहियों में 200 से अधिक शहरों में इसका विस्तार करने की योजना है। कंपनी ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्पॉटीफाई के साथ साझेदारी और शैक्षिक पहल जैसे कई प्रयास किए हैं। हालांकि, माना जा रहा है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बड़ा मसला सुलझने के बाद ही असली बदलाव आया है। भले ही वीआई अभी भी कुल ग्राहकों और 4जी/5जी उपभोक्ताओं के मामले में रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से पीछे है, लेकिन यह लगातार वृद्धि कंपनी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देती है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

15 हजार रुपये मिले थे, मैंने पूरी रकम खर्च कर दी

टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय कप्तान ने सुनाया संघर्ष भरा किस्सा

नई दिल्ली, एजेंसी। सूर्यकुमार यादव इस समय अपने करियर के एक अलग दौर से गुजर रहे हैं। 2026 में भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान को अब भारतीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया है। हालांकि, सूर्यकुमार ने वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के साथ बातचीत में उन्होंने अपनी पहली कमाई और क्रिकेट के शुरुआती दिनों के संघर्ष को याद किया। सूर्यकुमार ने बताया कि मुंबई की अंडर-15 टीम के साथ अपने पहले दौरे के दौरान उन्हें पूरे सीजन के लिए सिर्फ 15,000 रुपये मिले थे। उस समय उनके पास किसी कंपनी का बैट स्पॉन्सर भी नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी कमाई क्रिकेट का सामान खरीदने में लगा दी थी।

सूर्यकुमार यादव ने अपनी पहली कमाई को याद करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार मुंबई के लिए अंडर-15 क्रिकेट खेला था, तब मुझे 15,000 रुपये मिले थे। यह पूरे दौरे के लिए थे। मैंने शायद पूरी रकम खर्च कर दी थी। उस समय मेरे पास बैट का कोई स्पॉन्सर नहीं था, इसलिए मैं अपनी पूरी कमाई क्रिकेट का सामान खरीदने में खर्च करता था।' उनका यह बयान बताता है कि भारतीय क्रिकेट के मौजूदा स्टार ने अपने शुरुआती दिनों में किस तरह सीमित संसाधनों के बीच क्रिकेट का सफर तय किया।

वर्ल्ड कप जिताने के बाद टीम से बाहर

सूर्यकुमार ने 2026 में भारत की कप्तानी करते हुए टीम को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया था। यह भारत का तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब था और लगातार दूसरा खिताब भी था। इससे पहले भारत ने 2007 में एमएस धोनी और 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में यह ट्रॉफी जीती थी। हालांकि, वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही महीनों बाद सूर्यकुमार को भारतीय टी20 टीम से बाहर कर दिया गया। चयनकर्ताओं ने अगले दो साल के चक्र को ध्यान में रखते हुए टीम में बदलाव का फैसला किया और श्रेयस अय्यर को कप्तानी की जिम्मेदारी दी।

खराब फॉर्म बनी बड़ी वजह

सूर्यकुमार की बल्लेबाजी में लगातार निरंतरता की कमी भी चयनकर्ताओं के फैसले की एक वजह मानी गई। 2026 के आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके बावजूद सूर्यकुमार का कहना है कि वह भारतीय टीम में वापसी के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने वापसी के सवाल पर कहा, 'देखिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं और वह सब कुछ कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। अगर चीजें अच्छी होती हैं, तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाएगा।'

ईशान भैया को नहीं पता था कि मैं विकेट टेकर हूं

नईदिल्ली, एजेंसी। दलीप ट्रॉफी में ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रनों से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री मार ली है. इस बड़ी जीत में टीम के उपकप्तान वैभव सूर्यवंशी का बल्ला भले ही खामोश रहा, लेकिन उन्होंने अपनी फिरकी से 2 अहम विकेट झटककर महफिल लूट ली. मैच के बाद इस युवा स्टार ने अपनी घातक गेंदबाजी के राज से पर्दा उठाया और बताया कि आखिर किस मास्टर प्लान के तहत उन्होंने विरोधी बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया. वैभव सूर्यवंशी को फैन्स विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानते हैं. ऐसे में इस युवा खिलाड़ी ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया.

दरअसल, नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ खेले गए मैच में जब ईस्ट जोन के गेंदबाजों को विकेट निकालने में संघर्ष करना पड़ रहा था, तब कप्तान ईशान किशन ने वैभव को गेंद थमाई. ईशान को लग रहा था कि यह एक रिस्क है, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर वैभव ने सिर्फ 3 ओवर में 11 रन देकर 2 अहम विकेट चटका दिए और अपने कप्तान को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया. बीसीसीआई डोमेस्टिक द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में अपनी इस शानदार गेंदबाजी पर बात करते हुए वैभव ने मजेदार खुलासा किया. उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी बल्लेबाज से पूछें तो उसे गेंदबाजी करने में मजा आता है. विरोधी टीम के विकेट नहीं गिर रहे थे, इसलिए मुझे 2-3 ओवर फेंकने को कहा गया.

51 साल की उम्र में आइल ऑफ मैन की क्रिकेटर ने इतिहास रच दिया

नईदिल्ली, एजेंसी। जोआन हिक्स को क्रिकेट करियर शुरू करने में लगभग आधी सदी लग गई। उन्होंने 47 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया। चार साल बाद 51 साल की उम्र में आइल ऑफ मैन की इस क्रिकेटर ने इतिहास रच दिया। वह 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाली सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी बन गईं। ग्रीस की महिला टीम के खिलाफ दाएं हाथ की ऑफ-स्पिनर हिक्स ने तीसरी बार टी20 इंटरनेशनल में फाइव-विकेट हॉल लिया। उन्होंने 10 रन देकर पांच विकेट लेकर करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया। हिक्स घातक गेंदबाजी के कारण ग्रीस 15 ओवर में 52 रन सिमट गई। आइल ऑफ मैन ने पावरप्ले में नौ विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। 51 साल और 173 दिन की उम्र में, हिक्स इंटरनेशनल क्रिकेट (पुरुष या महिला) में 50 साल की उम्र के बाद पांच विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गईं। हिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के बर्ट आयरनमोंगर का 96 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में यह मुकाम हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गईं। लेफ्ट आर्म स्पिनर आयरनमोंगर ने 1932 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49 साल और 314 दिन की उम्र में पांच विकेट लिए थे। इत्तेफाक से, उन्होंने दोनों पारियों में पांच विकेट लिए थे। पहली पारी में 6 रन देकर पांच विकेट और दूसरी पारी में 18 रन देकर छह विकेट झटके। प्रोटियाज टीम एक पारी से हारी थी। वह ऑस्ट्रेलिया के 153 रन के जवाब में 36 और 45 रन पर आउट हो गई थी।

नीरज चोपड़ा को लगी टखने की चोट

एशियन गेम्स से हुए बाहर, डायमंड लीग फाइनल और वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में भी नहीं ले पाएंगे हिस्सा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 2026 के बाकी सीजन में प्रतिस्पर्धा करते नजर नहीं आएंगे। ट्रेनिंग के दौरान टखने में लिगामेंट फटने के बाद दो बार के ओलंपिक पदक विजेता को अगले महीने जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स से भी बाहर होना पड़ा है। चोट के कारण वह डायमंड लीग फाइनल और पहली बार आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट

नीरज चोपड़ा ने शनिवार को अपने अकाउंट पर पोस्ट कर चोट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर और अपनी टीम से चर्चा के बाद उन्होंने 2026 सीजन के बाकी हिस्से से हटने का फैसला किया है। नीरज ने लिखा, 'कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे वह लय मिलती महसूस हो रही थी, जिसकी मैं तलाश कर रहा था। सीजन का सर्वश्रेष्ठ श्रो करने के बाद मुझे लगा कि मेरी गति वापस आ रही है। दुर्भाग्य से, इसके कुछ समय बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने में लिगामेंट फट गया। डॉक्टर और टीम से चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि मैं इस सीजन के बाकी हिस्से में हिस्सा नहीं लूंगा।'

डायमंड लीग फाइनल से बाहर

इस चोट का सीधा असर नीरज के आगामी बड़े मुकाबलों पर पड़ा है। वह 5 सितंबर को ब्रसेल्स में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा 11 से 13 सितंबर तक बुडापेस्ट में होने वाली पहली वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप भी वह मिस करेंगे।नीरज के लिए सबसे बड़ा झटका अगले महीने जापान में होने वाले एशियन गेम्स से बाहर होना है। वह इस प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक की बड़ी उम्मीद माने जा रहे थे।2026 का सीजन नीरज चोपड़ा के लिए पहले से ही मुश्किल रहा था। सितंबर 2025 से परेशान कर रही लोअर बैक इंजरी के कारण उनकी प्रतिस्पर्धी वापसी जून तक टल गई थी। वापसी के बाद भी वह पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर अपनी लय हासिल करने के संकेत दिए।

मुझे कोई अनुचित फायदा नहीं मिला

मारिजाने कैप की आलोचना पर अनाया बांगर ने तोड़ी चुप्पी, दिया करारा जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर ने दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर मारिजाने कैप की आलोचना पर जवाब दिया है। कैप ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनाया को ऑस्ट्रेलिया में महिला घरेलू क्रिकेट के रास्ते के लिए मंजूरी दिए जाने पर सवाल उठाते हुए इस फैसले को गलत बताया था।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाया को तत्काल प्रभाव से कम्युनिटी और प्रीमियर क्रिकेट खेलने के लिए पात्र माना है। हालांकि, यह मंजूरी अपने आप में किसी टीम में चयन की गारंटी नहीं है। उन्हें क्लब स्तर पर प्रदर्शन के जरिए आगे के अवसर हासिल करने होंगे।

पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए

कैप की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अनाया ने कहा कि इस मुद्दे पर आपत्ति जताने वाले लोगों को पहले इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'जो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, उन्हें वास्तव में पहले इस विषय के बारे में खुद को शिक्षित करना चाहिए।' अनाया ने आगे कहा, 'मैंने पहले ही यह जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है कि मुझे कोई अनुचित फायदा नहीं है और मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से तय किए गए दिशानिर्देशों का पालन कर रही हूं।'

जैस्मिन: कड़ी मेहनत के बल पर बनाई पहचान

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा था। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक जीते थे। इसमें पुरुष और महिला दोनों मुक्केबाजों ने स्वर्ण जीते थे। स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों में एक नाम जैस्मिन लंबोरिया का भी था। लंबोरिया ने 57 किग्रा भारवर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली जैस्मिन लंबोरिया का जन्म 30 अगस्त 2001 को भिवानी, हरियाणा में हुआ था। भिवानी को 'लिटिल क्यूबा' के नाम से जाना जाता है। यह स्थान मुक्केबाजी का गढ़ है। जैस्मिन के लिए मुक्केबाजी के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला आसान नहीं था। लड़की होने की वजह से उन्हें परिवार और समाज की रूढ़िवादी सोच से जूझना पड़ा, लेकिन एक बार सभी का विश्वास हासिल करने के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैस्मिन को अपने सफर में चाचा संदीप और परविंदर का भी बाद में साथ मिला, दोनों बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे हैं। भिवानी की लैंबोरिया बॉक्सिंग अकादमी में जब जैस्मिन ने प्रशिक्षण शुरू किया, उस समय वहां कोई महिला मुक्केबाज नहीं थी। इसलिए उन्होंने लड़कों के साथ प्रशिक्षण लिया, जिसने उनकी तकनीक और आत्मविश्वास को और मजबूत किया।

प्रतिभा का लोहा मनवाया

जैस्मिन ने 2021 में दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसी वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में रजत पदक और 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 60 किग्रा लाइटवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने अस्ताना में 2025 में आयोजित विश्व बॉक्सिंग कप में जैस्मिन ने गोल्ड मेडल जीत वैश्विक मंच पर अपनी श्रेष्ठता साबित की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का स्वर्ण पदक उनकी सबसे हालिया सफलता है। 25 साल की हो रही जैस्मिन से एशियन गेम्स और ओलंपिक में पदक की उम्मीद है।

एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना लक्ष्य: आशी

भोपाल, एजेंसी। भारतीय राइफल शूटर आशी चौकसे ने साल 2018 में अचानक प्रतिस्पर्धी शूटिंग शुरू की थी। अब 24 वर्षीय आशी अपने दूसरे एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने अब तक एशियन गेम्स में एक कांस्य और दो रजत पदक जीते हैं। अब उनका बड़ा लक्ष्य आइची-नागोया 2026 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना है। आशी ने 2022 एशियन गेम्स (जो 2023 में हुए थे) में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत, महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3पी टीम इवेंट में रजत और महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3पी इवेंट में कांस्य पदक जीता था। उन्हें लगता है कि यहां मुकाबला करने से जापान में होने वाले अगले इवेंट के लिए उनकी समझ और आत्मविश्वास बेहतर हुआ है। अपने पहले और दूसरे एशियन गेम्स के सफर के अंतर पर बात करते हुए आशी ने कहा, 'एशियन गेम्स ओलंपिक के बाद सबसे बड़े मल्टी-स्पोर्ट टूर्नामेंट में से एक है और मैं वहां पहले भी मुकाबला कर चुकी हूं। मैंने उस मंच पर परफॉर्म किया है, इसलिए मुझे पता है कि इसके लिए क्या चाहिए।

एशियन गेम्स तक के सफर में कड़ी ट्रेनिंग शामिल थी, जिसके दौरान भारतीय शूटिंग टीम ने भोपाल में इंटेंसिव कैंप में हिस्सा लिया। शुरुआती कैंप में कई मैच और फाइनल सिमुलेशन के साथ-साथ लंबे शूटिंग सेशन भी शामिल थे, जिनका मकसद एथलीटों की सहनशक्ति और निरंतरता को परखना था। आशी ने कहा, 'हम तैयारी में बहुत मेहनत और कोशिश कर रहे थे। इस कैंप की रणनीति मैच और फाइनल आयोजित करने की थी। हमने लगभग तीन-चार मैच और तीन-चार फाइनल खेले, जो 10 दिन के कैंप में बहुत अधिक हैं। मैच खेलना बहुत इंटेंस होता है, भले ही वह सिर्फ 60-शॉट का मैच हो। हमने 120-शॉट का मैच भी खेला, जो किसी प्रोग्राम में नहीं होता, लेकिन हमने इसे लंबे समय तक सहनशक्ति और स्थिरता की जांच करने के लिए किया, ' शूटिंग टीम ने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलकर काम किया है।

मियांदाद बोले-इमरान खान भ्रष्ट नहीं, उन्हें रिहा किया जाए

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद अपने साथी क्रिकेटर और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में बात करते हुए रो पड़े, जो जेल में बंद हैं। 1975 और 1996 के बीच छह वर्ल्ड कप खेलने वाले मियांदाद ने कहा कि इमरान खान भ्रष्ट नहीं हैं। उन्हें ईमानदार बताते हुए उनकी रिहाई की गुहार लगाई। 2018 और 2022 के बीच देश के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाए जाने के बाद 2023 में जेल भेजा गया था।मियांदाद ने इमरान खान को लेकर नैरेटिव यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वह एक ईमानदार आदमी है। वह कोई ऐसे इंसान नहीं हैं जो भ्रष्ट काम करता हो, वरना उन्होंने बहुत कुछ किया होता। अगर आप उन्हें बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा? क्या वह किसी को खाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? वह भी किसी के बेटे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि वह क्या कर रहे होंगे।'

इमरान खान के मेडिलक जांच के बाद मियांदाद का आया बयान

69 साल के जावेद मियांदाद का बयान इमरान खान के इस्लामाबाद में मेडिकल जांच के तुरंत बाद आया, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। इमरान खान की पार्टी ने मेडिकल जांच के तरीके पर सवाल उठाया। उसने कहा कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ट्रांसफर करने और उनके निजी डॉक्टर समेत डॉक्टरों की एक टीम की मौजूदगी की इजाजत दी थी।

दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन टीम में नजर आएंगे गुरनूर बरार

नई दिल्ली, एजेंसी। तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को रविवार से बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ जोन के खिलाफ शुरू होने वाले दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन की टीम में शामिल किया गया है। गुरनूर श्रीलंका के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा थे। गुरनूर को नॉर्थ जोन की प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की संभावना है। भारतीय टीम मैनेजमेंट अगले दौरों से पूर्व उन्हें रेड बॉल में ज्यादा से ज्यादा मौके देना चाहता है। गुरनूर भारत की पिछली दो टेस्ट टीमों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनका टेस्ट डेब्यू अभी बाकी है। जुलाई में, वह इंडिया ए के श्रीलंका के शैडो टूर पर गए थे, और दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट में 145 रन देकर 10 विकेट लिए थे। गुरनूर के प्रथम श्रेणी करियर के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो वह 19 मैचों में 25.24 की औसत से 62 विकेट ले चुके हैं। 23 साल के गुरनूर ने जून में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया और भारत के हाल के इंग्लैंड दौरे पर तीनों वनडे मैच खेले। वह अब तक 6 वनडे मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं।

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जम्मू और कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी का चयन भी भारतीय टीम में हुआ था। हालांकि, उन्हें भी डेब्यू का मौका नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक नबी अपने वीजा पेपरवर्क के पूरा होने पर इंग्लिश काउंटी सर्किट में खेलने की सोच रहे हैं। चयनकर्ता भी चाहते हैं कि नबी तेज गेंदबाजों के लिए आसान हालात में कुछ मैच खेलें। नबी को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी मौका मिल सकता है, ऐसे में उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा मौके देने पर टीम मैनेजमेंट विचार कर रहा है। अगर काउंटी में खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो नबी 22 सितंबर से पुडुचेरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया ए के दो मैचों में से पहले मैच में खेलेंगे, और फिर 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर में रेस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईरानी कप मैच के लिए जम्मू-कश्मीर टीम में शामिल होंगे। नबी ने जम्मू-कश्मीर को 2025-26 में रणजी ट्रॉफी की ऐतिहासिक खिताबी जीत में यादगार भूमिका निभाई थी और सीजन में 60 विकेट लिए थे।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

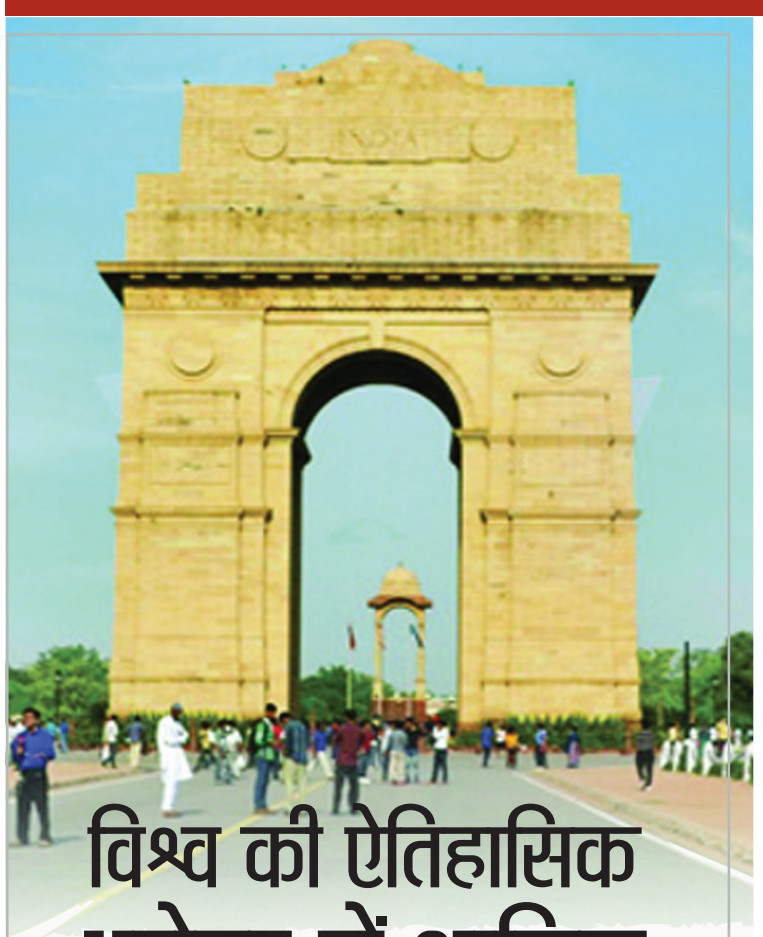

विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है इंडिया गेट

इंडिया गेट जो विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल एक द्वार है और यह दिल्ली में स्थित है.हर साल लाखों सैलानी इस द्वार को देखने आते हैं.हर साल 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट के सामने गणतंत्र दिवस की परेड कराई जाती है.

जी हां दोस्तों आज का हमारा लेख इंडिया गेट से संबंधित है.आज हम आपको इंडिया गेट से जुड़े वे सभी रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं पढ़े होंगेतो चलिए जानते हैं

- इंडिया गेट की ऊंचाई 43 मीटर है विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है.
- क्या आप जानते हैं इंडिया गेट को प्राचीन समय में किंग्सवे के नाम से जाना जाता था और इसका डिजाइन सर एडवर्ड लुटियन्स ने बनाया था.
- इंडिया गेट के सामने स्थापित छतरी में जार्ज पंचम की एक मूर्ति स्तापित थी जिसे बाद में यहाँ से हटाकर कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया था.
- आपको जानकर गर्व होगा इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद हुऐ 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था.
- क्या आप जानते है इंडिया गेट पर 13300 अधिकारियों और सौनिकों के नाम अंकित हैं.
- इंडिया गेट के नीचे चारों कोनों पर अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है जिसे वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में स्तापित किया गया था.
- क्या आप जानते है इंडिया गेट की नींव 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इस स्मारक को बनने में पूरे 10 वर्षों का समय लगा था.
- इंडिया गेट को देखने के लिए भारतीय टूरिस्टो के साथ साथ विदेशी सैलानी भी इस द्वार पर आते है.
- शाम के समय इंडिया गेट के चारों ओर लगी रोशनियों से इसे जगमगा दिया जाता है.जिससे एक भव्य दृश्य बनता है जो हमारी आँखों को एक सुखद अहसास देता है.
- आप इस स्मारक के पास से राष्ट्पति भवन को भी निहार सकते है.

अब मछली नहीं उड़ती

बहुत पुरानी बात है। उन दिनों मछलियां तैरने के साथ उड़ भी सकती थीं। मछली का मन करता, तो वह दूर आसमान में जा उड़ती। तैरने का मन करता, तो नदी के अंदर चली जाती।

एक दिन बगुले का जोड़ा कहीं जा रहा था। बगुला मछली से बोला, हमारे अंडों का ध्यान रखना। हम किसी से मिलकर आते हैं।

दोपहर हुई, तो मोर ने मछली से कहा, मोरनी न जाने कहां चली गई? उसे ढूंढ़ने जा रहा हूं। हमारे अंडों का ध्यान रखना। उन सबके लौटने तक मछली ने अंडों का ध्यान रखा।

शाम हुई, तो चुहिया ने मछली से कहा, मैं घूमने जा रही हूं। मेरे बच्चे अकेले हैं। मछली पहरा देने लगी। चुहिया रात को लौटी। मछली जाने को हुई, तो गिलहरी ने आवाज लगाई, अमरूद पक गए होंगे, तो मुझे बताना।

मछली उड़ी और अमरूद के पेड़ के फल देख आई। फिर गिलहरी को बताया, अमरूद पक चुके हैं।

मछली जाने लगी, तो एक सांप ने पूछा, कहां जा रही हो?

मछली बोली, अब थक गई हूं। पानी में तैरने जा रही हूं।

सांप ने हंसते हुए कहा, आज की थकान तो दूर हो जाएगी। मगर कल क्या होगा?

मछली ने चौंकते हुए पूछा, मतलब?

सांप ने जवाब दिया, मतलब यह है कि हर कोई तुम पर रोब जमाता है। मोर, बगुले, चुहिया, गिलहरी तक तुम से अपना काम करा लेते हैं। क्यों?

मछली सोच में पड़ गई।

सुबह हुई। बगुले का जोड़ा मछली के पास आया और वही बात कहकर उड़ चला। मछली को सांप की बात याद थी। उसने मुंह बनाया, हुंह! मैं नदी में तैरने जा रही हूं। शाम तक बाहर नहीं आऊंगी।

बस फिर क्या था। सांप को इसी पल का इंतजार था। बगुलों के वापस आने से पहले वह उनके अंडे खा चुका था।

दोपहर हुई, तो मोर ने मछली से कहा, मोरनी न जाने फिर कहां चली गई। मैं उसे ढूंढ़ने जा रहा हूं। अंडों का ध्यान रखना। मछली ने मोर की बात को अनसुना कर दिया। वह घने पेड़ के पीछे आराम करने लगी। सांप ने मोरनी के अंडों को भी चट कर डाला।

शाम हुई, तो चुहिया ने मछली को बुलाया। रोज की तरह वह टहलने चली गई। मछली उड़ी और आसमान में गायब हो गई। अब सांप चुहिया के बच्चों को निगल गया।

रात हुई, तो गिलहरी ने मछली से कहा, अमरूद पक गए हैं। मैं भी कुछ अमरूद खा आती हूं। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। गिलहरी के जाते ही मछली ने नदी में गोता लगाया। वह तैरती हुई नदी के दूसरे तट पर जा पहुंची। सांप ने गिलहरी के बच्चों को भी अपना निवाला बना लिया।

सुबह हुई, तो सभी ने मछली को घेर लिया। बगुला आगबबूला होकर चिल्लाया, मेरे अंडे कहां हैं?

चुहिया और गिलहरी ने अपने बच्चों के बारे में पूछा। मछली ने जवाब दिया, मुझे क्या पता?

बगुले को गुस्सा आ गया। उसने मछली को दबोच लिया। मछली ने डरते-डरते सारा किस्सा सुनाया।

किस्सा सुनकर चुहिया बोली, एक सांप की बातों में आकर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें उड़ने लायक नहीं छोड़ूंगी। चुहिया ने मछली के पंख कुतर डाले। गिलहरी ने कहा, आज से तुम उड़ नहीं पाओगी। मछली नदी में जा छिपी।

बगुला बोला, कहां जाती हो। मैं तुम्हें पानी में भी नहीं छोड़ूंगा। तभी से बगुला मछली की ताक में रहता है। वहीं मछली अब उड़ नहीं पाती है।

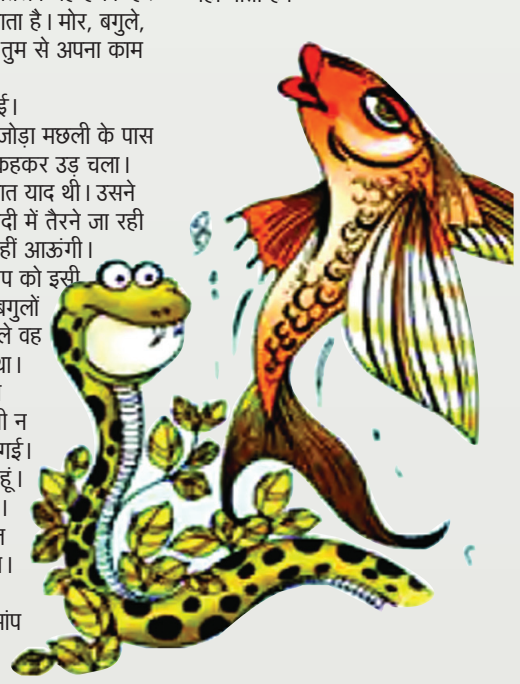

बादलों का सीना चीरकर उड़ने वाले पक्षी बाज के बारे में आप भली-भांति जानते होंगे.बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है और इसके साथ ही यह पक्षी बहुत तेज रफ्तार से उड़ता है. उदाहरण के तौर पर बाज 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक उड़ सकता है.

आसमान का राजा बाज

बाज आसमान में लगभग 12000 फीट ऊंचा उड़ सकता है यह बारिश के दिनों में हमेशा बादलों के ऊपर उड़ता है शायद इसीलिए इसे आसमान का राजा भी कहा जाता है. बाज हवा में एक जगह मंडरा सकते हैं जैसे एक पतंग हवा में एक जगह उड़ती रहती है.एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार बाज की नजर बहुत तेज होती है यह अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है साथ ही इनकी आंखों में इन्फ्रारेड सिस्टम विकास हो गया है जिसकी वजह से यह है शिकार के शरीर से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर उसका शिकार कर सकता है.बाज की नजर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बाज को आसमान से ही पानी में तैरती हुई मछली दिखाई दे जाती है और बाज पानी में गोता लगाकर मछली को पकड़ सकता है.

बाज की चोंच एक अलग तरह से बनी होती है इनकी चोच 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होती है चोच के दोनों तरफ एक छोटा दांत बाहर निकला हुआ होता है.यह अपने शिकार को देखते हैं लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार की तरफ बढ़ते है.और जैसे ही कोई मेंढक या चूहा पकड़ते है तो उसकी गर्दन पर ऐसी जगह पर वार करते है जिससे उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है. जिसे शिकार मुकाबला नहीं कर पाता है और मारा जाता है.बाज अपने से दो गुना बड़े शिकार को पकड़ सकता है, कभी-कभी यह अपने से इतने बड़े शिकार को पकड़ लेते हैं कि एक बार में उसे खा भी नहीं पाते है.क्थद्दद्यद्द शिकार करके अपने भोजन को ऊंची पहाड़ियों में बने अपने घोसलों में छोड़ देते है. और बाद में जब इन्हें भूख लगती है तब यह उस शिकार को आ कर खा लेते है.बाज की आंखें अपने शिकार को बिना पलक झपकाए अधिक समय तक देख सकती हैं इसी कारण ये अपने शिकार से कम ही चुकते है. बाज एक मांसाहारी पक्षी होता है इसका भोजन सांप, मछली, मेंढक, खरगोश, चूहे और छोटे पक्षी होते है. यह पक्षी लगभग पूरी दुनिया में ही पाया जाता है यह ज्यादातर ऊंची पहाड़ियों और चट्टानों पर अपना घोंसला बनाते है लेकिन ज्यादातर बाज पक्षी दूसरे पक्षियों के घोंसलों पर कब्जा करके यह रहते है.विश्व भर में इसकी 60 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है.एक वयस्क बाज का वजन लगभग 10 किलो तक हो सकता है.इसके फल का आकार में बहुत बड़े और पतले होते हैं जिसके कारण यह ज्यादा देर तक हवा में उड़ पाते है.मादा बाज पक्षी साल में एक बार 3 से 4 अंडे देती है और जब तक उनमें से उसके बच्चे नहीं निकल आते है वह उनके ऊपर बैठी रहती है. बाज के बच्चे अंडे में से औसतन 35 से 40 दिनों के अंदर बाहर निकल आते है.एक बाज की औसतन आयु 60 से 70 वर्ष होती है.उनके पंख और सोच लगातार बढ़ती रहती है इसलिए जैसे-जैसे यह व्यस्त होते है. इन्हें अपनी चोच से भोजन खाने में दिक्कत होने लगती है इसीलिए यह चट्टानों पर जाकर अक्सर अपनी चोच घिसते रहते है.इनके पंजों की बात करें तो पैर के पंजे बहुत ही ताकतवर और नुकीले होते हैं जिससे यह किसी भी सांप या मछली को अगर एक बार पकड़ ले तो उसके बाद छोड़ते नहीं है.यह पक्षी ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है.

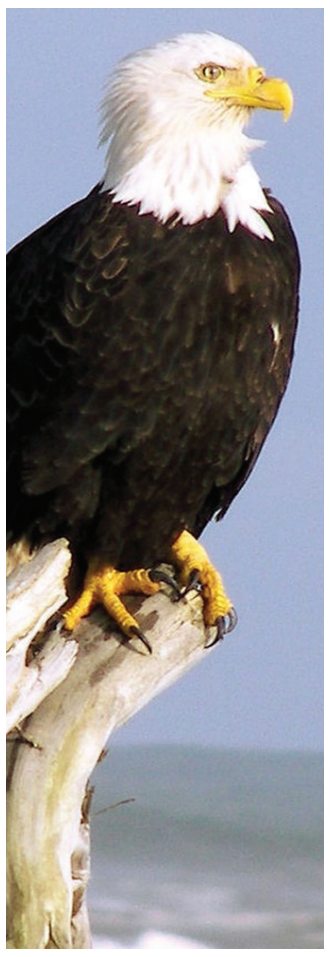

- बाज पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है.
- बाज एक मांसाहारी पक्षी है.
- यह मुख्य रूप से भोजन में सांप, मछली, चूहा, मेंढक इत्यादि खाते है.
- बाज आसमान में बिना पंखों को हिलाएं हवा में अधिक समय तक उड़ सकता है.
- यह लगभग दुनिया के हर देश में पाया जाता है और दुनिया भर में इसकी 60 से अधिक प्रजातियां अभी तक खोजी जा चुकी है.
- यह पक्षी अकेले में जंगलों में पहाड़ियों के ऊपर रहना पसंद करता है.
- क्या आप जानते हैं जब भी पक्षियों के राजा की बात आती है तो उनमें बाज का नाम सबसे पहले लिया जाता है.क्योंकि यही एक मात्र ऐसा पक्षी है जो तेज रफ्तार के साथ ही शारीरिक रूप से भी सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है.
- बाज मांसाहारी जीवो की श्रेणी में आता है और इसका जीवनकाल लगभग 40 वर्ष से लेकर 70 वर्ष का होता है.
- बाज तेजी से उड़ने और सतह पर चलने की लिए भी जाना जाता है. यह पक्षी सतह पर भी गजब की तेजी से दौड़ता है.
- बाज के शरीर की बनावट जैसे छाती की मजबूत मांसपेशियाँ , लम्बे पंख और स्ट्रीमलाइन आकार के फाल्कन सही मायने में इस पक्षी को गजब की रफ्तार देने के लिए ही बने है.
- बाज के शरीर की लंबाई 13 से 23 इंच तक हो सकती है तथा बाज क पंखो लंबाई 29 से 34 इंच तक होती है.इसके साथ ही मादा बाज का आकार नर बाज से बड़ा होता है.
- बाज के पसंदीदा शिकारो में चिड़िया, कबूतर, चूहा ८ बत्तख इत्यादि का शिकार ज्यादातर करता है.
- बाज आकाश में 12000 फीट की उंचाई तक उड़ान भर सकता है
- क्या आप जानते है बाज की अब तक लगभग 2000 प्रजाति खोजी जा चुकी है.
- अगर आप बाज को नहीं पहचानते तो इसे जानने के लिए नीली स्लेटी और उसी रंग के लम्बे नुकील पंखो और पेट पर सफेद एवं काले धब्बो से पहचाना जा सकता है.
- आपको जानकर हैरानी होगी द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों द्वारा भेजे संदेशो को रोकने के लिए घुमन्तु बाज का इस्तेमाल किया जाता था.
- जंगलो में रहने वाले आदिवासी ज्यादातर छोटे -छोटे पक्षियों के शिकार के लिए बाज का सहारा लेते हैं.
- बाज एक ऐसा पक्षी है जो अंटार्टिका के इलावा समूचे विश्व में पाया जाता है.
- बाज ही एकमात्र ऐसा शिकारी पक्षी है जो शिकार के लिए इंसान के 2 साल के बच्चे को भी उठा कर ले जा सकता है.
- मादा बाज 1 से लेकर 3 अंडे देती है और लगभग बाज 34 से 36 दिनों तक अण्डों पर बैठती है जिसके बाद अण्डों में से बच्चे बाहर निकल आते हैं
- क्या आप जानते है एक स्वस्थ बाज 6 किलोग्राम वजन को उठा कर हवा में उड़ सकता है.
- जिस तरह बाज तेजी का प्रतिक माना जाता है ठीक इसी प्रकार बाज के बच्चे का भी बहुत तेजी से विकास होता हैं यह 6 सप्ताह में 3-4 किलो हो जाता हैं.
- बाज की नजर भी बहुत तेज होती है उदाहरण के तोर पर यह अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी पर भी देख लेता है.

प्रति सेकंड 130 फ्रेम देख सकता है पेरग्रिन बाज

पशु-पक्षियों की दुनिया में पेरग्रिन बाज की दृष्टि सबसे तेज होती है। एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के सबसे सामान्य परभक्षी पक्षियों में शुमार यह बाज एक सेकंड में लगभग 130 फ्रेम देख सकता है। स्वीडन की लुंड यूनिवर्सिटी सहित कई शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी तुलना में इंसान प्रति सेकंड अधिकतम 50-60 फ्रेम ही देख पाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई शख्स मूवी थिएटर में बतौर फिल्म प्रति सेकंड 25 छवियों की गति ही देख सकता है। वह भी उसे छवियों की शृंखला के रूप में नहीं देख सकता है। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, पेरग्रिन बाज की दृष्टि सबसे तीव्र होती है। तेज प्रकाश वाले वातावरण में उसकी दृष्टि 129 एचजेड (प्रति सेकेंड पलक झपकाना) होती है। इन्हीं परिस्थितियों में सेकर बाज 102 एचजेड और हैरिस की देखने की क्षमता 77 एचजेड होती है। ऐसा पहली बार है, जब वैज्ञानिकों ने परभक्षी पक्षियों की दृष्टि की गति का अध्ययन किया है। इसके लिए उन्होंने यह गणना की कि वे कितने दृश्यों का अनुभव कर सकते हैं। अध्ययन के सह लेखकों में एक लुंड यूनिवर्सिटी के एल्मट केल्बर ने कहा, 'मेरे सहयोगी साइमन पोटियर और मैंने सेकर और हैरिस प्रजाति के बाजों का अध्ययन किया। इस दौरान यह भी गणना की कि ये कितनी तेज रोशनी में झपकी ले सकते हैं।' शोधकर्ताओं ने कहा कि परभक्षी पक्षियों की नजर शिकार की जरूरत के हिसाब से हरकत करती है। आमतौर पर बाज तेज गति से उड़ने वाली पक्षियों का शिकार करते हैं और अपनी तीव्र दृष्टि से उन पक्षियों के सचेत होने से पहले ही उन्हें पकड़ लेते हैं।

350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार करता है

शोधकर्ताओं ने बताया कि हैरिस नामक बाज के पास अत्यधिक ऊंचाइयों पर शिकार करने के लिए बहुत तेज दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि वह जमीन पर छोटे और धीमी गति वाले जानवरों का शिकार करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, पेरग्रिन बाज के पास अलग-अलग दृश्यों में खुद की दृष्टि को समायोजित करने की क्षमता होती है, क्योंकि यह एक फॉर्मूला वन रेसिंग कार की गति यानी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार पर हमला बोलती है।

पिंजरे में रखे गए पक्षियों की स्थिति समझने में मिलेगी मदद

यह अध्ययन छोटे कीटों को खाने वाली पक्षियों की देखने की क्षमता का पता लगाने के लिए किया गया है। शोधकर्ताओं ने का कहना है कि बाजों के शिकार की कला यह भी बताती है कि परभक्षी पक्षियों की दृष्टि बहुत तीव्र होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस अध्ययन से मिली नई जानकारी से कैद में रखे गए पक्षियों की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

अजीब है कस्तूरी बैल

बैल के बारे में आप लोग तो कुछ न कुछ जानते ही होंगे। लेकिन आप लोगों को आज एक ऐसे बैल के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते हों। यह बैल है कस्तूरी बैल। है न रोचक बात! आप लोग मस्क डीयर यानी कि कस्तूरी हिरण के बारे में जानते होंगे, लेकिन कस्तूरी बैल के बारे में नहीं। यह बैल भले ही अपने यहां नहीं पाया जाता, लेकिन यह कुछ एक देशो में पाया जाता है।

कस्तूरी बैल बिल्कुल याक जैसा दिखता है। यह वृक्षहीन टुन्ड्रा प्रदेश और आर्कटिक प्रदेशों का निवासी है। पूर्वी अलास्का से लेकर उत्तरी कनाडा तक और ग्रीनलैंड में पाया जाता है।इसकी दो प्रजातियां होती हैं। एक ग्रीनलैंड मस्क ऑक्स या व्हाइट फेस्ड मस्क ऑक्स। दूसरी प्रजाति केनेडियन हाई-आर्कटिक मस्क ऑक्स होती है।

दिखता है याक जैसा

यदि आप इसे दूर से देखो तो आप को भ्रम हो जाएगा। आपको लगेगा कि यह याक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका शरीर काफी गठीला होता है। उस पर फर की दोहरी परत होती है। बाहरी परत लम्बे-लम्बे फर वाली होती है। कभी-कभी इसके बाल इतने लम्बे होते हैं कि जमीन को भी छूने लगते हैं। इनके मोटे फरों का रंग गहरा भूरा होता है। इनके फर ही बर्फीले आर्कटिक की शीत लहरों में ठंड से बचाव करते हैं। इनके बाल भेड़ के बालों की तरह ऊन बनाने के काम आते हैं। इनके फर गर्मी के मौसम में झड़ने लगते हैं।

विशालकाय शरीर

इसके कंधों पर कूबड़ होता है। इसके सींग लम्बे,चौड़े और मुड़े हुए होते हैं। इसके खुर बैलों से काफी बड़े होते हैं। इसके विशालकाय शरीर का वजन 200 किलोग्राम से 400 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि शरीर की लम्बाई छह फुट से साढ़े सात फुट के मध्य होती है और ऊंचाई पांच फुट तक होती है। इसके गठीले शरीर के कारण ही शिकारी जानवर जल्दी हमला नहीं कर पाते। ये अक्सर झुंड में ही रहते हैं, इसलिए शिकारी जानवरों पोलर बीयर, आर्कटिक फॉक्स और आर्कटिक भेड़ियों से अपनी रक्षा कर लेते हैं।

नहीं खाता मांस

आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्फ में रहने की वजह से इसका भी भोजन मांस होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं है। घास, आर्कटिक फूल, मरकट और बहुत प्रकार की वनस्पति खाता है। वैसे इसे 'विलो प्लांट' खाना ज्यादा अच्छा लगता है। यह अपना भोजन चबाता नहीं है, बल्कि उसे निगल जाता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

चीन के सिचुआन प्रांत में लगे भूकंप के झटके

बीजिंग, एजेंसी। भूकंप के झटके बाद नेपाल में फ्लड फ्लैश से मची तबाही के बीच चीन में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। चीन के सिचुआन प्रांत स्थित लोंगचांग शहर शुक्रवार को 5.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के तेज झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर ने भूकंप की पुष्टि करते हुए बताया कि लॉन्गचांग शहर में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र लॉन्गचांग शहर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दर्ज किए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है और प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि चीन में भूकंप की खबर ऐसे समय में आई है, जब पड़ोसी देश नेपाल पहले से ही बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। ज्ञात हो कि चीन के सिचुआन प्रांत में पहले भी कई बार भूकंप आ चुके हैं, इसलिए यहां लोग भूकंप को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। शुक्रवार को लगे भूकंप के झटके से फिलहाल किसी तरह के नुकसान या जनहानि को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

पहली विदेश यात्रा पर भारत आएंगे पीएम बालेन शाह, नेपाली वित्त मंत्री का बड़ा एलान

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने गुरुवार को बताया कि पदभार संभालने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की करेंगे। हालांकि, वागले ने अभी तारीख नहीं बताई, लेकिन वागले ने संकेत दिया है कि अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो शाह इस साल के अंत से पहले भारत आ सकते हैं। इस दौरान दौरान स्वर्णिम वागले ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को 100 अरब डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य, भारतीय और नेपाली रुपये की विनिमय दर, हालिया बाढ़ राहत कार्यों और प्रधानमंत्री बालेन शाह की कार्यशैली पर भी विस्तार से चर्चा की। वागले ने कहा, पदभार ग्रहण करने के बाद बालेन का पूरा ध्यान घरेलू मुद्दों पर ही केंद्रित था। हमारे शुरुआती 100 दिन 100 सूत्री एजेंडे पर केंद्रित रहे, जिसमें हमने खुद को 87.2 प्रतिशत अंक दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद हमने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर चर्चा शुरू की। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की ही होगी। हालांकि, तारीखों पर अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह दौरा इसी साल के अंत से पहले होगा। कार्यक्रम में मौजूद भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस घोषणा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, नेपाल और भारत के संबंधों की नींव इतनी मजबूत है कि इन्हें पासपोर्ट या सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अगर आज वागले ने यह स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह की पहली विदेश यात्रा भारत की होगी, तो यह दर्शाता है कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते किस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण संदेश है। गौरतलब नेपाल में इसी साल मार्च महीने में हुए आम चुनाव में बालेन शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी जीत हासिल की। जिसके बाद बालेन शाह ने 27 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

कनाडा को चिढ़ाने के चक्कर में फिर ट्रोल हुआ व्हाइट हाउस, उल्टा पड़ा बाज और हंस की फोटो का दांव

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे कूटनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच कनाडा को नीचा दिखाने के लिए एक बाज द्वारा कनाडाई हंस को दबोचने की फोटो पोस्ट की, जिसमें एक अमेरिकी बाज (गंजा बाज) कनाडाई हंस को दबोचे हुए दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिकी ताकत का प्रतीक बनाकर शेयर किया, लेकिन यह कूटनीतिक दांव उल्टा पड़ गया। क्योंकि जिस वीडियो से यह तस्वीर ली गई थी, उसमें अंततः कनाडाई हंस ने ही पलटवार कर बाज को खदेड़ दिया था। दरअसल, व्हाइट हाउस द्वारा शेयर की गई तस्वीर का मकसद यह था कि अमेरिका एक शक्तिशाली बाज की तरह हावी है और कनाडा की बत्तख हार मान चुकी है। हालांकि, गोवा के एक प्रवासी द्वारा रिकॉर्ड किए गए मूल फुटेज ने इस कहानी का पूरा पासा ही पलट दिया। बर्फ पर करीब 20 मिनट तक चले इस हवाई संघर्ष में कनाडाई बत्तख ने ऐसा पलटवार किया कि अंततः अमेरिकी गंजे बाज को हार मानकर वहां से उड़ना पड़ा। यह अद्भुत दृश्य 23 फरवरी 2025 को ओंटारियो के बर्लिंगटन में मर्विन सेक्वेरा ने अपने कैमरे में कैद किया था। मूल रूप से गोवा के रहने वाले मर्विन कनाडा बसने के बाद एक उत्साही वन्यजीव फोटोग्राफर बन गए हैं। घटना की जानकारी देते हुए मर्विन सेक्वेरा ने ग्लोबल न्यूज को बताया कि उन्होंने बाज को हंस पर बार-बार हमला करते देखा था।

नेपाल की प्रलयंकारी बाढ़ में अपनों की तलाश, फोन की घंटी बजने के इंतजार में कटी परिजनों की रातें

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल-तिब्बत सीमा पर रसुवा जिले में संदिग्ध ग्लेशियर फटने से आई प्रलयंकारी बाढ़ ने एक पवित्र यात्रा को भीषण त्रासदी में बदल दिया है। भोटे कोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में मलबे व पत्थरों के तेज बहाव से मची तबाही इतनी भयंकर थी कि भूकंपीय मॉनिटरों पर भी कुछ पल के लिए हलचल दर्ज की गई। इस भीषण प्राकृतिक आपदा ने न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि सात समंदर पार अमेरिका में बसे भारतीय-अमेरिकी परिवारों को भी असहनीय इंतजार और गहरे संकट में धकेल दिया है।

इस हिमालयी तबाही ने नेपाल में कितना नुकसान पहुंचाया है : नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) की छठी स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, भोटे कोशी बाढ़ के बाद अब तक 389 शव बरामद किए जा चुके हैं और 977 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में नेपाली सेना, पुलिस व आव्रजन विभाग के 105 सुरक्षाकर्मियों के साथ 517 विदेशी नागरिक और विदेशों में रहने वाले 127 नेपाली शामिल हैं। इस अचानक आई भीषण बाढ़ की आपदा में 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और परिवहन से लेकर बिजली व संचार के बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है।

अपनों की तलाश में भटक रहे परिवारों पर क्या गुजर रही है : अमेरिका में रह रहे कई भारतीय-अमेरिकी परिवार इस समय गहरे मानसिक आघात और अपनों की खोज में पल-पल तड़प रहे हैं। न्यूयॉर्क के शशिधरन श्रीधरन की पत्नी रेखा और 14 वर्षीय बेटी राशि कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर बुधवार को नेपाल लौटने वाली थीं, लेकिन तभी यह आपदा आ गई। श्रीधरन ने इसे अपने जीवन के सबसे बुरे 48 घंटे बताया है। इसी तरह वर्जीनिया के ऋत्विक रंगू अपने पिता और डॉ. राधिका शर्मा अपने बुजुर्ग माता-पिता (65 वर्षीय रमेश शर्मा और 64 वर्षीय नीलम शर्मा) की सुरक्षित वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। न्यूयॉर्क में नेपाल के महावाणिज्य दूत दधिराम भंडारी ने बताया कि उन्होंने 25 से अधिक लापता अमेरिकी नागरिकों (जिनमें से अधिकांश भारतीय मूल के हैं) की सूची नेपाल के विदेश मंत्रालय को भेजी है। राहत और बचाव के लिए जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के अनुसार स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है और पूरी सरकारी मशीनरी खोज और बचाव में जुटी है। खोज अभियान में 13,295 सुरक्षाकर्मियों और 15 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। इनकी मदद से अब तक 1,976 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों के राहत कार्य के लिए तत्काल 2.5 करोड़ नेपाली रुपये (एनपीआर) भेजे हैं। इसके साथ ही, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने प्रभावित विदेशियों की मदद और समन्वय के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष (ईसीआर) स्थापित किया है। लापता भारतीयों की तलाश और सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका है? भारतीय विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, अब तक 84 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। इनमें त्रिशूली-द्ध परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री शामिल हैं। इस संकट में जयपुर फुट यूएसए जैसे संगठनों के नेता प्रेम भंडारी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो चौबीसों घंटे काम कर रहा है। वहीं, अध्यात्मिक गुरु स्वामी अवधेशानंद गिरि ने न्यूयॉर्क में राहत कार्यों की समीक्षा की और नेपाल को सहायता की पेशकश के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता की सराहना की। यह त्रासदी दिखाती है कि प्रकृति के रौद्र रूप के सामने मानवीय तंत्र कितने लाचार हो जाते हैं। फिलहाल, भारत, अमेरिका और नेपाल की सरकारें प्रभावितों तक पहुंचने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं। मलबे के बीच अपनों को सुरक्षित ढूंढने की यह जंग जारी है, और उनके परिवार इस उम्मीद में फोन थामे बैठे हैं कि जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी।

नेपाल की बाढ़ के बीच चीन के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर उठे सवाल, वायरल वीडियो ने खोली पोल : काठमांडू, बीजिंग, एजेंसी। नेपाल में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के बीच चीन द्वारा बनाए जा रहे हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बाढ़ से ठीक कुछ दिन पहले सामने आए एक ब्लॉगर के वीडियो ने इन परियोजनाओं की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल, नेपाल में आई भयानक बाढ़ आने से कुछ दिन पहले, एक ब्लॉगर ने नेपाल की तरफ़ बन रहे चीन के बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का वीडियो बनाया था। व्लॉगर ने नेपाल की ओर निर्माणाधीन विशाल चीनी जलविद्युत परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण किया था।

यूएन में भारत की दो-टूकः यूएन 80 पहल में विकास सर्वोच्च प्राथमिकता हो

न्यूयॉर्क, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरिष परवथानेनी ने बुधवार को यूएनडीपी प्रशासक के साथ संवाद किया। उन्होंने यूएनडीपी/ यूएनएफपीए/ यूएनओपीएस कार्यकारी बोर्ड के दूसरे सत्र को संबोधित किया। परवथानेनी ने कहा कि भारत यूएन80 पहल में विकास स्तंभ को सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संरचनाओं, कार्यबल और संचालन मॉडल को वर्तमान वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने का समर्थन करता है। उन्होंने मौजूदा प्रणालियों में अनावश्यक बदलावों के प्रति आगाह किया। परवथानेनी ने कहा, हमें ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो खराब नहीं है। भारत ने राष्ट्रीय स्वामित्व और देश-नेतृत्व वाले विकास मार्गों के महत्व पर जोर दिया। भारत का तर्क है कि समाधान बाहर से थोपे नहीं जाने चाहिए।

राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और बहुपक्षीय सहायता : भारत समग्र, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक वृद्धि मॉडल का पक्षधर है। यह राष्ट्रीय स्वामित्व और देश-नेतृत्व वाले विकास मार्गों पर केंद्रित है। भारत मानता है कि समाधान बाहर से तय नहीं होने चाहिए। इसके बजाय, उन्हें सदस्य देशों द्वारा पेश किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, क्षमताओं व परिस्थितियों से प्रेरित होना चाहिए। परवथानेनी ने जोर दिया कि साझेदार देशों की विकास प्राथमिकताओं का सम्मान हो। बहुपक्षीय सहायता उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप

रहनी चाहिए।

यूएनडीपी के साथ भारत का सहयोग : भारतीय राजदूत ने यूएनडीपी के साथ भारत के सहयोग को रेखांकित किया। भारत इंडिया-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष और भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) कोष के माध्यम से संगठन के साथ काम कर रहा है। इन कोषों से भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और जलवायु लचीलेपन के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक दिए हैं। सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) और छोटे द्वीप विकासशील देशों (एसआईडीएस) पर विशेष ध्यान है। ये पहल दक्षिण-दक्षिण सहयोग को दर्शाती हैं। यह विकासशील देशों को ज्ञान साझा करने, क्षमताएं जोड़ने, संसाधन जुटाने और बेहतर शर्तों पर पूंजी पाने में मदद करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के वित्तपोषण पर चिंता व्यक्त की, खासकर मुख्य वित्तपोषण में गिरावट पर। पारवथानेनी ने यूएनडीपी के लिए भारत की लगातार मुख्य योगदानकर्ता की भूमिका दोहराई।

रूसी बमबारी से दहली यूक्रेन की अर्थव्यवस्था

कीव, एजेंसी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष अब एक नए विनाशकारी आर्थिक मोर्चे पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह राजधानी कीव समेत नौ यूक्रेनी शहरों पर रूस ने मिसाइलों और ड्रोन की भीषण बारिश कर दी। साढ़े चार साल से जारी इस युद्ध में यह हमला न सिर्फ सैन्य ठिकानों पर, बल्कि यूक्रेन के निजी व्यवसायों और समग्र अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के इरादे से किया गया था। इस हमले में आम नागरिकों की जान जाने के साथ-साथ यूक्रेन की बिजली प्रणालियों, अनाज निर्यात बंदरगाहों और बड़े व्यापारिक गोदामों को भारी क्षति पहुंची है। रूस अब यूक्रेन के आर्थिक तंत्र को सीधी चोट पहुंचाने की नीति पर काम कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसे तेल रिफाइनरियों, लॉजिस्टिक्स हब और बंदरगाहों जैसे सैन्य-औद्योगिक ठिकानों पर कार्रवाई बताया। लेकिन असल चोट यूक्रेन के निजी व्यापार को लगी है। रूसी ड्रोन हमलों ने तीन बड़े वितरण केंद्रों को निशाना बनाकर खिलौनों की एक स्टोर चेन और एक चॉकलेट कंपनी के विशाल गोदामों को तबाह कर दिया, जबकि एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर का डिपो क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल, यूक्रेन के हालिया लंबी दूरी के ड्रोन हमलों से रूस को वित्तीय मुश्किलें हुई थीं, जिससे नाराज होकर रूस ने यूक्रेनी निजी उद्योगों पर यह हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने भी रूस के आर्थिक हितों पर सीधे हवाई हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन लगभग हर रात रूसी सीमा के भीतर सैकड़ों लंबी दूरी के ड्रोन दाग रहा है। हाल ही में रूस की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी वाइल्डबेरीज के गोदामों को तबाह करने के बाद यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर कंपनी ओजोन को अपना निशाना बनाया है। ओजोन के उफा स्थित लॉजिस्टिक्स केंद्र पर सीधा हमला किया गया, जबकि ऑरेनबर्ग सुविधा को सतर्कता चेतावनी के बाद खाली कराना पड़ा। उधर, रूसी हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने विभिन्न क्षेत्रों में यूक्रेन के 267 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया है। इस बमबारी ने यूक्रेन के नागरिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ओडेसा के बंदरगाह क्षेत्र में हुए सात घंटे लंबे हमले में एक विशाल अनाज गोदाम (ग्रेन एलीवेटर) क्षतिग्रस्त हो गया, जो यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भीषण ठंड से पहले बिजली ग्रिड को ठप करने की नीयत से दागे गए चार ग्लाइड बमों ने खेरसॉन के एक प्रमुख संयंत्र के जनरेटरों को नष्ट कर दिया, जिससे नाफ्तोगाज को प्लांट बंद करना पड़ा।

ट्रंप के डाक मतदान पर संकटः अमेरिकी कोर्ट ने आदेश पर फिर लगाई रोक

वाशिंगटन, एजेंसी। एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कार्यकारी आदेश को लागू करने की कोशिशों पर रोक लगा दी। इस आदेश में डाक मतदाता को सीमित किया गया था। इस कदम ने उस आदेश को दूसरी बार रोक दिया। यह सब तब हुआ जब मध्यावधि चुनावों के लिए पहला डाक बैलेट भेजे जाने में बस एक हफ्ता ही बचा था। अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने सरकार को दो हफ्ते तक इस आदेश को लागू करने से रोक दिया।

सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील किया जा सकता है: इस मामले को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले न्यायाधीशों ने एक प्रक्रियात्मक निर्णय सुनाते हुए तलवानी के उस पूर्व के फैसले को रद्द कर दिया था जिसने ट्रंप के आदेश को प्रभावी होने से रोक दिया था।

हाई कोर्ट ने पहले फैसला क्यों नही सुनाया : गुरुवार को आया यह फैसला डेमोक्रेट्स और

मतदान अधिकार समूहों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए अपने मुकदमों को फिर से दायर किया। उच्च न्यायालय के रूढ़िवादी बहुमत ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश की वैधता पर फैसला नहीं सुनाया, बल्कि यह कहा कि इसके खिलाफ कानूनी चुनौतियां हैं। जिनके कारण तलवानी ने शुरू में इसे रोक दिया था। इसे बहुत जल्दबाजी में दायर की गई थीं। नए औपचारिक नियम में क्या है? अब प्रशासन ने एक औपचारिक नियम जारी किया है, जो यह तय करेगा कि क्या अमेरिका डाक सेवा राज्यों के मेल बैलेट पहुंचाएगी या नहीं। इससे कानूनी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। उतार-चढ़ाव भरी इस कानूनी लड़ाई का मध्यावधि चुनावों पर बड़ा असर पड़ेगा। लगभग एक-तिहाई अमेरिकी डाक से वोट करते हैं। वहीं, चुनाव अधिकारियों का कहना है कि डाक सेवा के नए निर्देशों के मुताबिक अपने सिस्टम में बदलाव करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। डाक सेवा का कहना है कि वह डाक मतपत्रों तब तक डिलीवर नहीं करेगी, जब तक राज्य उन मतदाताओं की सूची नहीं देते, जिन्हें ये बैलेट मिलने चाहिए और लिफाफों को एक खास तरीके से तैयार नहीं करते। तलवानी ने गुरुवार को लिखा, मुकदमा करने वाले राज्यों के पास मिडटर्म चुनाव से पहले नए मेल बैलेट डिजाइन करने, नए डिजाइनों को मंजूरी दिलाने, मेल बैलेट के उत्पादन का ऑर्डर देने। अपने चुनाव प्रबंधन सिस्टम को अपडेट करने, यूएसपीएस पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग देने और पोर्टल पर नागरिकों का डेटा अपलोड करने के लिए न तो समय है और न ही फंड। इस मामले की सुनवाई 3 सितंबर को होनी है। डेमोक्रेट और मतदान अधिकार समूह का क्या कहना है? डेमोक्रेट और मतदान अधिकार समूह इस मांग को असंवैधानिक बताते हैं। उनका कहना है कि संविधान राज्यों और कुछ मामलों में कांग्रेस को चुनाव नियम बनाने का अधिकार देता है, न कि राष्ट्रपति या डाक सेवा को। इसी तर्क के आधार पर अदालतों ने ट्रंप के पहले कार्यकारी आदेश को रोक दिया था, जो पिछले साल जारी किया गया था और जिसमें चुनाव प्रक्रियाओं को बदलने की मांग की गई थी, जैसे कि पंजीकरण के लिए नागरिकता के दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता। राष्ट्रपति लंबे समय से डाक मतदान को निशाना बनाते रहे हैं, जिसके लिए वे झूठा आरोप लगाते हैं कि उन्हें 2020 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में पाया गया कि डाक द्वारा डाले गए प्रत्येक 10 मिलियन मतपत्रों में से केवल लगभग चार मामलों में ही धोखाधड़ी हुई थी।

भारत-कनाडा बातचीतः द्विपक्षीय निवेश संधि पर वार्ता को हरी झंडी, 2030 तक 4.65 लाख करोड़ के कारोबार का लक्ष्य

टोरंटो, एजेंसी। भारत और कनाडा के बीच आर्थिक संबंधों में नया अध्याय जुड़ रहा है। नई दिल्ली में मार्च 2026 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक की प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के वित्त मंत्रियों के बीच पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता संपन्न हुई। बैठक के बाद भारत ने कनाडा के साथ जल्द से जल्द द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई है। यह रणनीतिक कदम निवेश संबंधों को मजबूत करेगा और वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर यानी करीब 4.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस वार्ता का मुख्य ध्यान दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना रहा। दोनों पक्षों ने वर्ष 2030

तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कनाडाई डॉलर (करीब 4.65 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया है। यह महत्वपूर्ण कदम मार्च 2026 में नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक की प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। दोनों पक्षों ने वर्ष 2026 के अंत तक कनाडा-भारत व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) वार्ता को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। वित्त मंत्रियों-निर्मला सीतारमण और फ्रांसिस-फिलिप शैम्पेन ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और अपनी घरेलू नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा की। वार्ता में भारतीय बाजार में कनाडाई पेंशन फंडों की बड़ी मौजूदगी को रेखांकित किया गया और वित्तीय संस्थानों के बीच साझेदारी बढ़ाने पर बात हुई। दोनों पक्षों ने निवेशकों के लिए स्थिर और निश्चित घरेलू कर कानूनों की आवश्यकता को महत्वपूर्ण माना। संवाद में भुगतान प्रणालियों के आधुनिकीकरण, वित्तीय स्थिरता, फिनटेक इनोवेशन और वित्तीय अपराधों से निपटने पर सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें सबसे बड़ा कदम कनाडा में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के विस्तार का स्वागत करना है। इसके लिए स्थानीय भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी की जाएगी, जिससे सीमा पार प्रेषण (रेमिटेंस) तेज और सस्ता होगा। इसका लाभ दोनों देशों के बीच पर्यटन, शिक्षा, व्यापार और छोटे व मध्यम स्तर के उद्यमों (एमएसएमई) को मिलेगा।

व्हाइट हाउस में निर्माण बना सुरक्षा में रोड़ा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर मरीन वन और एक यात्री विमान के बीच इस महीने हुई करीबी घटना में व्हाइट हाउस में चल रहे निर्माण कार्य की भूमिका सामने आई है। संघीय जांचकर्ताओं के मुताबिक, निर्माण के कारण मरीन वन के रेडियो संचार में दिक्कत आ गई थी। इसी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से तीन मिनट पहले दी जाने वाली जरूरी चेतावनी नहीं सुन पाए। इसके बाद उन्होंने एक यात्री विमान को उड़ान भरने की अनुमति दे दी। यह घटना 4 अगस्त को वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई थी। उस समय ट्रंप को लेकर मरीन वन उड़ान भरने वाला था और दूसरी तरफ एनवॉय एयर का एक यात्री विमान टेकऑफ के लिए तैयार था। दोनों विमान कुछ समय के लिए काफी करीब आ गए थे। मामले में हुञ्रस्क्रकी जांच अभी जारी है और मौजूदा रिपोर्ट को प्रारंभिक रिपोर्ट माना जा रहा है।

पहले से सामने आ चुकी थी रेडियो की समस्या : राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, घटना से करीब एक सप्ताह पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मरीन वन के पायलटों के बीच बैठक हुई थी। इसमें पायलटों ने बताया था कि उड़ान से पहले दी जाने वाली सामान्य तीन मिनट की चेतावनी कंट्रोल टावर तक नहीं पहुंच रही थी। दोनों पक्षों ने तय किया था कि अगर रेडियो संपर्क में दोबारा समस्या आई तो किसी दूसरे व्यक्ति या स्थान के जरिए यह संदेश कंट्रोलरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन 4 अगस्त को यह वैकल्पिक व्यवस्था भी काम नहीं कर सकी। मरीन वन के पायलटों ने तीन मिनट पहले उड़ान की सूचना देने की कोशिश की थी, लेकिन रीगन एयरपोर्ट के कंट्रोलरों ने वह संदेश नहीं सुना।

कंट्रोलर को नहीं मिली जानकारी, यात्री विमान को मिली उड़ान की अनुमति : मरीन वन के पायलट ने रेडियो पर बताया था कि हेलीकॉप्टर तीन मिनट में उड़ान भरेगा। लेकिन एयरपोर्ट के आधिकारिक कंट्रोल रिकॉर्डिंग में यह चेतावनी दर्ज नहीं हुई। इसके चलते कंट्रोलर को यह पता नहीं था कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। इसलिए उन्होंने यात्री विमान को टेकऑफ की अनुमति दे दी। कुछ ही देर बाद कंट्रोलर को पता चला कि मरीन वन भी उड़ान भर रहा है। उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट को यात्री विमान के बारे में चेतावनी दी। मरीन वन के पायलटों ने भी विमान को देख लिया और सुरक्षित दूरी बनने तक कुछ समय के लिए अपनी उड़ान रोक दी। शुरुआती अनुमान के मुताबिक, दोनों विमान अपने सबसे नजदीकी बिंदु पर करीब 0.8 मील (1.3 किलोमीटर) की क्षैतिज दूरी और लगभग 700 फीट (215 मीटर) की ऊंचाई के अंतर पर थे। यात्री विमान के चालक दल को उड़ान भरने के तुरंत बाद अपने विमान के टकराव-रोधी सिस्टम से चेतावनी मिली थी। हालांकि, चालक दल ने हेलीकॉप्टर को अपनी आंखों से नहीं देखा।

ट्रंप खुद अपने सबसे अच्छे प्रवक्ताः कैरोलिन लेविट की उत्तराधिकारी को सलाह, व्हाइट हाउस प्रवक्ता पद से विदा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की निवर्तमान व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने आखिरी दिन अपने काम की व्यस्तता का जिक्र करते हुए कहा कि टेलीविजन पर दिखाई देने वाली प्रेस ब्रीफिंग उनके काम का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि 90 प्रतिशत काम पत्रकारों के फोन कॉल का जवाब देने में जाता है। लेविट ने कहा, लोग यह नहीं समझते कि इस नौकरी में ब्रीफिंग और टीवी पर मैंने जो किया, वह 10 प्रतिशत है। 90 प्रतिशत काम सुबह पांच बजे और रात 11 बजे तक आपके सभी फोन कॉल लेने का है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस हिस्से की कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन पत्रकारों के साथ रोजाना काम करने की याद आएगी।

लेविट ने अपने उत्तराधिकारी को क्या दी सलाह : इस दौरान कैरोलिन लेविट ने अपने उत्तराधिकारी को सलाह देते हुए कहा कि इस पद पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं। लेविट ने आगे कहा कि व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चिउंग और वह अक्सर मजाक करते थे कि ट्रंप ही व्हाइट हाउस के असल कम्युनिकेशन डायरेक्टर और प्रेस सेक्रेटरी हैं। कैरोलिन लेविट ने 27 अगस्त को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के रूप में अपना आखिरी दिन पूरा किया। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में इस पद पर रहने वाली सबसे कम उम्र की प्रेस सचिव थीं। उन्होंने परिवार और अपने छोटे बच्चों के साथ अधिक समय बिताने के लिए पद छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि, वह ट्रंप के बाहरी सलाहकार के तौर पर काम करती रहेंगी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने की जमकर तारीफ : कैरोलिन लेविट इस पद पर रहने वाली 36वीं प्रेस सचिव थीं। लेविट ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का मजबूती से

बचाव किया। व्हाइट हाउस ने उनके कार्यकाल के कई चर्चित पलों को याद करते हुए उनकी पत्रकारों के साथ तीखी बहस और सरकार की नीतियों के बचाव का जिक्र किया। वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिवों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ में से एक बताया।

पत्रकारों से तीखे सवाल-जवाब : लेविट कई बार पत्रकारों के साथ तीखे सवाल-जवाब को लेकर चर्चा में रहीं। एक मौके पर उन्होंने एक पत्रकार से कहा, आप लेफ्ट-विंग हैक हैं। आप पत्रकार नहीं हैं। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, क्या बेवकूफी भरा सवाल है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीति का भी बचाव किया और अवैध तरीके से अमेरिकी कानून तोड़ने वाले प्रवासियों को अपराधी बताया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर उन्होंने डेमोक्रेट्स और मुख्यधारा के मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी सैनिकों के मुद्दे पर उन्हें भाषण देने की जरूरत नहीं है।

फ्रांस और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर भी दिया था बयान : विदेश नीति के मुद्दों पर भी लेविट के बयान चर्चा में रहे। फ्रांस के एक राजनेता की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जुड़ी टिप्पणी पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि आज फ्रांस के लोग जर्मन भाषा नहीं बोल रहे हैं तो इसकी वजह अमेरिका है। उन्होंने डेमोक्रेट्स और मुख्यधारा के मीडिया पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप भी लगाया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले अमेरिकी शहरों में अपराध को लेकर भी उन्होंने बयान दिए। लेविट ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के स्वास्थ्य और उनकी काम करने की क्षमता को लेकर भी पूर्व प्रशासन और मीडिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े कवरअप और राजनीतिक घोटालों में से एक बताया था।

ट्रंप पर हमले के बाद टाली थी मैटरनिटी लीव : लेविट ने ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास के बाद अपनी मैटरनिटी लीव भी कुछ समय के लिए टाल दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगा था कि वह आखिरी बार सवालों का जवाब दे रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर हमले के बाद उन्हें लगा कि प्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। अपने कार्यकाल में लेविट ने नए मीडिया संस्थानों और पत्रकारों को भी व्हाइट हाउस ब्रीफिंग रूम में जगह दी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप का संदेश हर जगह पहुंचाना उनकी टीम के लिए जरूरी है। इस बीच ट्रंप ने नए प्रेस सचिव को लेकर एक संभावित नाम की ओर इशारा किया है। हाल ही में फॉक्स न्यूज की संवाददाता एलेक्सिस मैकएडम्स ने ट्रंप से पूछा कि लेविट की जगह कौन ले सकता है। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में मैकएडम्स से ही पूछा, आप? इसके बाद उन्होंने कहा, आप कैसी रहेंगी? ट्रंप ने मैकएडम्स के काम की भी तारीफ की और कहा कि उन्हें वह हमेशा पसंद रही हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)